PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 200 ● भिलाई, शनिवार 14 फरवरी 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

बापू ने बचा लिया! नाबालिग से रेप के दोषी की उम्रकैद 12 साल में बदली

मुंबई । बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी की उम्रकैद की सजा को घटाकर 12 साल कर दिया है। अदालत ने यह नरमी दोषी की कम उम्र, लंबे समय तक जेल में बिताए गए वक्त और वहां उसके आचरण में आए सुधार को देखते हुए बरती है। खास बात यह है कि दोषी ने जेल में रहते हुए महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित निबंध प्रतियोगिता और अध्ययन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था, जिसे कोर्ट ने उसके सुधरने का एक सकारात्मक संकेत माना है। जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की खंडपीठ ने 2 फरवरी को दिए अपने आदेश में साल 2016 में हुए इस अपराध के लिए दोषी की सजा को बरकरार तो रखा, लेकिन उसकी अवधि को कम कर दिया। दोषी ने विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि अपराध के वक्त दोषी की उम्र महज 20 साल थी और उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था।

तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा गिरफ्तार, एसओजी ने दबोचा

कानपुर। कानपुर के बहुचर्चित लेम्बोर्गिनी हिट एंड रन मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे और मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसओजी की टीम ने उसे हिरासत में लिया है। वह पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था और अब थोड़ी ही देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह हादसा 8 फरवरी की दोपहर वीआईपी रोड पर हुआ था, जहां तेज रफ्तार लेम्बोर्गिनी ने बुलेट और ऑटो को टक्कर मार दी थी, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे। इस हाई-प्रोफाइल मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी पक्ष की ओर से कई कानूनी दांव-पेच खेले गए। पहले एक ड्राइवर मोहन एम की ओर से कोर्ट में सरेंडर अर्जी लगाई गई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि वह स्थायी ड्राइवर है और घटना के वक्त वही कार चला रहा था।

पटना सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, तीसरी बार मचा हड़कंप

पटना। पटना सिविल कोर्ट को गुरुवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल के जरिए पूरे कोर्ट भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसकी सूचना मिलते ही एहतियातन अदालत परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने सिविल कोर्ट के तीनों प्रवेश द्वार बंद कर दिए और किसी भी व्यक्ति के अंदर आने पर रोक लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंच गई।

बांग्लादेश चुनाव-20 साल बाद सत्ता में लौटी बीएनपी

बीएनपी को मिला पूर्ण बहूमत,तारिक रहमान बनेंगे प्रधानमंत्री

ढांका/ एजेंसी

बांग्लादेश की राजनीतिक फिज़ा में दो दशकों के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। 13 फरवरी, 2026 को आए चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि तारीक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में शानदार वापसी कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 300 सदस्यीय संसद में बीएनपी ने 151 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर 'पूर्ण बहुमत' हासिल कर लिया है। यह जीत बीएनपी के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पार्टी करीब 20 साल बाद फिर से देश की कमान संभालने जा रही है। 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद वतन लौटे तारिक रहमान के लिए यह चुनाव व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़ी जीत साबित हुआ है। उन्होंने दो महत्वपूर्ण सीटों बोगुरा-6 और ढाका-17 पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है। ढाका-17 सीट पर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार को 4,399 वोटों से हराया। जीत की आधिकारिक घोषणा के बीच खबर यह भी मिली है कि तारीक रहमान शनिवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संसद परिसर में शपथ समारोह की तैयारियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अपनी इस बड़ी सफलता के बाद रहमान ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की है और फिलहाल किसी भी विजय रैली के बजाय जुमे की नमाज के बाद दुआ करने का निर्देश दिया है। बीएनपी की इस जीत पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीक रहमान को फोन पर बधाई दी और कहा कि यह

जीत बांग्लादेश की जनता के उनके नेतृत्व पर अटूट भरोसे को दर्शाती है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भारत एक लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के साथ मिलकर साझा विकास लक्ष्यों पर काम करना जारी रखेगा। इसके साथ ही अमेरिका और पाकिस्तान के नेतृत्व ने भी चुनाव को सफल बताते हुए रहमान को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग के अनुसार, इस 13वें संसदीय चुनाव में कुल 60.69 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस बार संसद में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है, जहां सात महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की जिनमें से छह बीएनपी के टिकट पर संसद पहुंची हैं। इनमें अफरोजा खान रीता और बैरिस्टर रूमिन फरहाना जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। 20 नवंबर 1965 को जन्मे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेता और पार्टी के चेयरमैन हैं। वह पार्टी की सर्वोच्च राजनीतिक इकाई का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। वे बांग्लादेश के इतिहास में एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता जिया उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिनकी 1981 में हत्या हो गई थी। उनकी मां बेगम खालिदा जिया 1991 से 1996 व 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं।

पीएम मोदी ने कहा- लोकतांत्रिक बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा भारत

बांग्लादेश के आम चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भारी जीत मिली है। इस जीत पर नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी और भरोसा दिलाया कि भारत हमेशा बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। जानकारी के अनुसार, तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं और संभावना है कि वह बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश में हुए पार्लियामेंट्री चुनावों मेंबीएनपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए वह तारिक रहमान को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह जीत बांग्लादेश की जनता का उनके नेतृत्व पर विश्वास दर्शाती है।

कांग्रेस सांसद विवेक ने दिखाया बड़ा दिल

शिवराज के खिलाफ सभी मानहानि केस लिए वापस

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाए सभी मानहानि के केस वापस ले लिए हैं। उसके बाद आज जब संसद में उनका आमना-सामना हुआ तो अंदाज कुछ अलग ही रहा। जहां शिवराज सिंह चौहान उनके साथ विनम्र नजर आए, वहीं विवेक तन्खा भी अपने दोस्ताना अंदाज में उनसे मिले। मिलने के बाद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर कहा कि सभी मामले खत्म (सर्वोच्च न्यायालय में मेरे द्वारा वापस लेने के पश्चात) ?शिवराज सिंह चौहान जी के साथ संसद में पहली मुलाकात। मध्य प्रदेश मूलत: मित्रता का ना की शत्रुता के भाव का प्रदेश है। पब्लिक लाइफ में हम सब को बड़ा दिल रखना चाहिए। दरअसल, सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कई मौकों पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि से जुड़े कानूनी मामले दर्ज कराए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव-2026' में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए.

कोर्ट से सभी केसों में मिली जमानत

जल्द बेउर जेल से बाहर आएंगे सांसद पप्पू यादव

नई दिल्ली। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी जीत सामने आई है। उन्हें उनके खिलाफ चल रहे सभी लंबित मामलों में अदालत से जमानत मिल गई है। लंबे समय से कानूनी दांव-पेंचों का सामना कर रहे सांसद के समर्थकों में इस खबर के बाद खुशी की लहर है। पप्पू यादव ने हमेशा इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया था। अब सभी मामलों में बेल मिलने के बाद वे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने संसदीय क्षेत्र और जनता के बीच सक्रिय हो सकेंगे। दरअसल, सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पटना के अलग-अलग थानों समेत पूर्णिया में दर्ज तीन मामलों में जमानत मिल गई है। इनमें गर्दनीबाग और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से जुड़े केस भी शामिल हैं। अदालत से बेल मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

सीडीएस ने मैकमोहन लाइन का जिक्र कर कही ये बात

चीन संग पंचशील समझौता क्यों चाहते थे नेहरू-अनिल चौहान.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

चीन और भारत के संबंधों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं। देश की आजादी के बाद बीते 78 वर्षों में चीन के प्रति भारत सरकार की नीति क्या रही है? इस विषय पर भूराजनीतिक मामलों के जानकारों के साथ-साथ सामरिक विषयों की समझ रखने वाले विशेषज्ञों की भी रूचि रही है। चीन के साथ पंचशील समझौते की जरूरत और इसके पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे? इस सवाल पर भारत के मौजूदा सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल अनिल चौहान ने बयान

दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'नेहरू को शायद इस बात की जानकारी थी कि पूर्वोत्तर भारत में मैकमोहन लाइन जैसी कोई चीज अस्तित्व में है। शायद इसी कारण उन्होंने पंचशील समझौता करने का फैसला लिया। चीन को लेकर आजाद भारत की पहली सरकार की नीतियों का जिक्र होने पर जनरल चौहान ने कहा कि साल 1954 में तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दी और दोनों पड़ोसी देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे भारत ने औपचारिक संधि के माध्यम से उत्तरी सीमा पर हुए विवाद के स्थायी समाधान की तरह देखा। जनरल चौहान ने कहा, चीन का रूख भारत से अलग था। उनका मानना था कि यह समझौता केवल व्यापार के लिए किया गया था और इसे भारत से लगने वाली सीमा को लेकर चीन का रूख नहीं माना जा सकता है।

'मां-बाप की मौत पर भी नहीं आए विदेश गए कई युवा',राज्यसभा में भाजपा सांसद ने दिया सुझाव

नई दिल्ली। राज्यसभा में एक बेहद मानवीय विषय रखा गया। इसके तहत सुझाव दिया गया कि विदेश जाने वाले लोगों से एफिडेविट लिए जाएं। इस एफिडेविट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि विदेश जाने वाले युवा अपने माता-पिता की देखभाल करेंगे और उनसे नियमित संपर्क बनाए रखेंगे। राज्यसभा में बताया गया कि हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां विदेश में रह रहे युवाओं ने बुजुर्ग माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। यहां तक कि भारत में रह रहे माता-पिता की मृत्यु होने पर भी वे नहीं आए। भाजपा सांसद राधा मोहनदास अग्रवाल ने राज्यसभा में यह विषय रखा।

किसान संघ के नेताओं से की अचानक मुलाकात

राहुल गांधी ट्रेड डील के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में... ?

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी छीनेगा और देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करने वाला है। राहुल गांधी ने लोकसभा में व्यापार समझौते को किसान विरोधी बताया है। इस कड़ी में अब शुक्रवार (13 फरवरी) राहुल गांधी ने किसान संघों के नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में

देश भर के किसान संघों के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का विरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता के साथ-साथ किसानों और कृषि मजदूरों की आजीविका की रक्षा करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने बताया कि बैठक के दौरान किसान संघ के नेताओं ने अपना विरोध जताया और मक्का, सोयाबीन, कपास, फ्लैक्स और मेवे उगाने वाले किसानों की आजीविका के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। पार्टी ने कहा गया है कि किसान नेताओं और राहुल गांधी ने इस समझौते का विरोध करने और किसानों-कृषि मजदूरों की आजीविका की रक्षा करने के लिए एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर चर्चा की। बता दें कि राहुल गांधी से मिलने वाले किसान नेताओं में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल एस खैरा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन, हरियाणा के अशोक बलहारा।

सेवा तीर्थ से नई शुरुआत-पीएम मोदी ने संभाला नया कार्यालय

मोदी ने पहले दिन किसानों और महिलाओं के लिए किए बड़े फैसले

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को औपनिवेशिक दौर की पहचान रहे साउथ ब्लॉक से अपने नए कार्यालय 'सेवा तीर्थ' परिसर में कार्यभार संभाल लिया। यह दिन खास भी रहा, क्योंकि 13 फरवरी को ही वर्ष 1931 में नई दिल्ली को औपचारिक रूप से आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में उद्घाटित किया गया था। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ परिसर पहुंचकर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को एक ही स्थान पर समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने परिसर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सेवा तीर्थ की दीवार पर देवनागरी में इसका नाम अंकित है और नीचे 'नागरिक देवो भव' का मंत्र लिखा गया है, जो नागरिक-केंद्रित शासन की भावना को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नए कार्यालय से काम शुरू करते ही प्रधानमंत्री ने कई अहम फैसलों पर हस्ताक्षर किए। इनमें 'पीएम राहत योजना' की शुरुआत शामिल है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि समय पर उपचार के अभाव में किसी की जान न जाए। सरकार पहले ही तीन करोड़ 'लखपति दीदी' का लक्ष्य हासिल कर चुकी है, जो निर्धारित समयसीमा से एक वर्ष पहले पूरा हुआ। अब

प्रधानमंत्री ने मार्च 2029 तक इस संख्या को बढ़ाकर छह करोड़ करने का नया लक्ष्य तय किया है। यह कदम महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 'कृषि अवसंरचना कोष' को बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने और किसानों को बेहतर भंडारण व प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नवाचार और उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' को 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य डीप टेक, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और शुरुआती चरण के नवाचारों को वित्तीय सहयोग देना है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नवनिर्मित परिसर 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होगा। करीब 1,189 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह परिसर 2,26,203 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के खाली होने के बाद साउथ ब्लॉक और उसके साथ वाले नॉर्थ ब्लॉक को सुरक्षित रखने की एक बड़ी योजना है। इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों को 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' नाम से एक भव्य सार्वजनिक संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा।

आधुनिक सुविधाएं और कम होगी ट्रैफिक की समस्या

विजय चौक के नजदीक बना यह नया कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। वैसे तो कैबिनेट की बैठकें प्राय: प्रधानमंत्री आवास (7 लोक कल्याण मार्ग) पर होती आई हैं, लेकिन नए 'सेवा तीर्थ' परिसर में विशेष रूप से एक कैबिनेट हॉल तैयार किया गया है। इसी परिसर के पास नया प्रधानमंत्री आवास भी बनाया जा रहा है, जो संसद भवन के काफी करीब है। इस पूरी शिफ्टिंग का एक मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के मूवमेंट को सुगम बनाना और उनके आवागमन के दौरान आम जनता को होने वाली ट्रैफिक संबंधी परेशानियों को कम करना है।

एम् मनू इंग्लिश मिडियम स्कूल देवभोग में मनाया गया वार्षिकोत्सव

देवभोग। प्रति वर्ष की भांति इस बार भी एम.मानू स्कूल देवभोग के द्वारा वार्षिकउत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कि शुरुवात सर्व प्रथम दीप प्रज्वलित कर विद्या कि देवी सरस्वती वंदना कर शुरुवात कि गई स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत के साथ अतिथियों का स्वागत किए तत्पश्चात एम मन्नू स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर, मंचाशीन अतिथियों और दर्शकों का दिल जीत लिया , बच्चों ने अलग-अलग भेष-भूसा के साथ अलग- अलग राज्य के संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए, सभी लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिए। कार्यक्रम में उपस्थिति मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर ने बच्चों के इस

मनमोहक प्रस्तुति कि सराहना करते हुए कहां कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अपने दैनिक दिनचर्या में इस तरह के कार्यक्रम को जरूर शामिल करना चाहिए। इस बीच कार्यक्रम को उपस्थिति विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश तिवारी ने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन कि प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धक किया और शिक्षा के साथ-साथ छात्रों के कौशल विकास के लिए इस तरह कि गतिविधियों के महत्व का उजागर होना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थिति देवभोग बीईओ देवनाथ बघेल ने बच्चों कि इस मनमोहक प्रस्तुति कि सराहना कि और कहां कि समय समय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए ताकि बच्चों के प्रतिभा में निखार आती है और बच्चों का झिझक दूर होता है अंत में एम मन्नू पब्लिक स्कूल के प्राचार्य मांडवी मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थिति सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए छात्रों के इस प्रदर्शन कि प्रशंसा कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचयात अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश तिवारी, विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुशील यादव जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल , प्रमेश अवस्थी, नगर पंचायत देवभोग के पार्षदों के साथ मिडिया साथी और पालकों कि उपस्थिति ने कार्यक्रम कि शोभा बढ़ाए।

वजन त्यौहार-2026 : आंगनबाड़ी केंद्र बाजार पारा नगरी में बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष आयोजन

नगरी। वजन त्यौहार-2026 के अंतर्गत 09 फरवरी, सोमवार को नगर के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 06, बाजार पारा नगरी में बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के वजन की नियमित जांच कर उनके शारीरिक विकास का आंकलन करना तथा अभिभावकों को संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर नगर पंचायत के पार्षद हरीश साहू एवं अल्का साव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों का वजन लेकर स्वयं निरीक्षण किया तथा माताओं को बच्चों के पोषण स्तर सुधारने के लिए हरी सब्जियों, फल, दूध एवं घर पर बने पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देने की सलाह दी। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुलोचना साहू, माद्री साहू, ललिता गौर, यामिनी नाग, मितानीन अनीता यादव, सहायिका अमृता लाहोरिया तथा गुलेश्वरी सोम की सक्रिय सहभागिता रही। इनके द्वारा बच्चों की लंबाईङ्कवजन मापकर स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज किया गया और कम वजन वाले बच्चों की पहचान कर विशेष निगरानी की जानकारी दी गई। वजन त्यौहार में वार्डवासी परनिया, गोदावरी, महेश्वर पटेल, ऋतु पटेल, प्रभा निषाद, कविता, छाया, पूजा सहित अनेक नागरिकों एवं अभिभावकों की उपस्थिति रही। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाथीबाहरा में फाइलेरिया मुक्त अभियान का शुभारंभ, 20 गांवों में चलेगा विशेष जागरूकता कार्यक्रम

कवर्धा। शिखर युवा मंच के संस्था प्रमुख भूपेश वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि एसबीआई फाउंडेशन एवं एसबीआई. एसजी ग्लोबल के सहयोग से संचालित जीवनम् मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के अंतर्गत महासमुंद जिले के विकासखंड बागबाहरा के 20 चयनित गांवों में निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। परियोजना का उद्देश्य दूरस्थ एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य के प्रति जनजागरूकता को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाथीबाहरा में फाइलेरिया मुक्त अभियान का शुभारंभ प्रभारी किशोर साहू द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक संचालित होगा। इसकी शुरुआत ग्राम हाथीबाहरा एवं छुरीडबरी से की गई है तथा शेष 19 गांवों में भी क्रमवार अभियान चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य समुदाय को फाइलेरिया रोग के लक्षण, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव उपायों के प्रति जागरूक करना तथा सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) के माध्यम से रोग की रोकथाम सुनिश्चित करना है। अपने संबोधन में श्री साहू ने आमजन से स्वास्थ्य विभाग द्वारा वितरित दवाओं का अनिवार्य रूप से सेवन करने की अपील की, ताकि क्षेत्र को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम में 142 बच्चों सहित सरपंच श्रीमती निशा चंद्राकर, प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक गोविंद चौधरी, मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक खेमचंद चक्रधारी, टेका संकुल प्रभारी शेखर चंद्राकर, बीआरपी श्रीमती रूखमणी साहू, मितानिन खिलनतीन, पार्वती एवं दुलारी चंद्राकर सहित स्वास्थ्य विभाग एवं समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एसबीआई संजीवनी टीम से जिला समन्वयक संदीप राव मोहिते, फार्मासिस्ट ओमप्रकाश चंद्रा, लैब टेक्नीशियन सुश्री साक्षी बैरागी, स्टाफ नर्स सुश्री अंजली राजपूत, किशन साहू, लील सिंह, रोहित कुमार.श्रीमती किरण नेताम, श्रीमती दिनेश्वरी ठाकुर तथा पायलट दिलहरण केवट ने सक्रिय भूमिका निभाई।

वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया गया प्रतिबंधित..

सक्ती। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्कूली एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा-13 में उल्लिखित विशेष अवसरों को छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं कोलाहल उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, पुरानी बस्ती पुलिया निर्माण को मिली करोड़ो की मंजूरी

जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया,क्षेत्र वासियो ने आभार जताया

धमतरी । कहते हैं कि लोग चुनाव जीतने के लिए अनेकों वादे करते हैं और चुनाव जीतते ही उन वादों को भुला देते हैं लेकिन नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार बलजीत छाबड़ा ने नगर वासियो से जिन वादों को किया था उनमे से बहुत से वादे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही पूर्ण हो गए। नगरी सहित आस पास के किसानों की सबसे पुरानी व महत्वपूर्ण मांग पुरानी बस्ती से मोदे मार्ग पर पुलिया निर्माण की।इस मांग को वर्षों से करते आ रहे किसानों के समक्ष कई जन प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आये और वादों के झूलों में झुलाकर चले गए किंतु पूल निर्माण का सपना हकीकत की धरातल पर नही उतर सका। कहते हैं न जब किसी कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठा लो तो वो पूरा होकर ही रहती है।वर्तमान नगर पंचायत के गठन पश्चात सबसे बड़ी मांगो में शामिल पुरानी बस्ती पुलिया निर्माण को आखिरकार अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा उपाध्यक्ष विकास बोहरा वार्ड पार्षद शंकर देव हरिसे साहू असकरण पटेल सहित सभी पार्षदों के प्रयास से 3 करोड़ 31 लाख 46 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है।जिससे नगरी सहित मोदे,खम्हरिया, बिरनपुर के कृषकों में हर्ष का माहौल है।इस पुलिया निर्माण की स्वीकृति से कृषकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है और उनकी समस्याओं का अंत होता नजर आ रहा है।पुरानी बस्ती सहित बिरनपुर मोदे के कृषकों ने बताया कि महानदी पर पुल नही होने से कृषि कार्यो में अत्यंत परेशानी होती थी।आवागमन के अभाव में कृषि कार्य प्रभावित होता था व लाखो रुपये की हानि प्रति वर्ष किसानों को होती थी साथ ही अनेक दुर्घटनाये घटित होती थी जिससे अब इनको निजात मिलेगी। महानदी पर पुरानी बस्ती मोदे मार्ग पर 3करोड़ 31 लाख 46 हजार के पुलिया निर्माण की स्वीकृति पर नगर पंचायत अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में यह सबसे बड़ी मांग थी जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने उपाध्यक्ष विकास बोहरा व पार्षदों के सहयोग से पूरा प्रयास किया जिसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विकास परक सोच ने मार्ग दिखाया व उप मुख्यमंत्री अरुण साव के किसानों के प्रति स्नेह ने तत्काल अमलीजामा पहनाया।जिले के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पित पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर,नगर निगम धमतरी महापौर रामु रोहरा,जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस के नेतृत्व व पूर्व विधायक द्वय पिंकी शिवराज शाह व श्रवण मरकाम के विकास परक मार्गदर्शन ने पुरानी बस्ती नगरी सहित क्षेत्र वासियो के लिए ये करोड़ो की सौगात प्राप्त हुई है।अध्यक्ष बलजीत छाबड़ा ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि चुनाव में किये गए सभी वादों को कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही पूर्ण करना और उनकी टीम इस दिशा में शत प्रतिशत खरा उतर रही है।

समावेशी शिक्षा के तहत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न

80 दिव्यांग विद्यार्थियों ने दिखाया उत्साह, प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

बेमेतरा। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, रायपुर के निर्देशानुसार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में निहित प्रतिभा को निखारने, उन्हें सम्मान प्रदान करने तथा उनकी क्षमताओं को उचित मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 फरवरी 2026 को शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, वार्ड क्रमांक 21 बेमेतरा में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के कुल 80 दिव्यांग विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अस्थि बाधित बच्चों के लिए 100 मीटर दौड़ एवं कुर्सी दौड़, श्रवण बाधित बच्चों के लिए गोला फेंक एवं 100 मीटर दौड़, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए निर्धारित ध्वनि लक्ष्य की ओर 25 मीटर दौड़ तथा मिश्रित मोतियों को अलग करने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए 50 मीटर दौड़ एवं सॉफ्ट बॉल थ्रो जैसे खेल कराए गए। प्रतियोगिता के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया गया।कार्यक्रम के सफल संचालन में जिले की समावेशी शिक्षा प्रभारी श्रीमती रेणुका चौबे, विकासखंड स्तर के क्क्क्क(द्धश्वष्ठ) एवं व्यायाम शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी गेंदराम चतुर्वेदी, जिला मिशन समन्वयक राज कुमार वर्मा, खेमराज साहू (एपीसी), प्रोग्रामर नेहिल वर्मा, समावेशी शिक्षा प्रभारी श्रीमती रेणुका चौबे सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह आयोजन समावेशी शिक्षा की भावना को सशक्त करते हुए समाज में समान अवसर और सहभागिता के संदेश को आगे बढ़ाने का प्रेरक प्रयास सिद्ध हुआ।

सिंघौरी मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत हुई सरस्वती साहू

प्रधानपाठक पद पर नियुक्ति होने पर स्टॉफद्वारा किया गया आत्मीय स्वागत

बेमेतरा। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघौरी में पदस्थ वरिष्ट शिक्षिका सरस्वती साहू की प्रधान पाठक के पद पर सिंघौरी स्कूल में पदोन्नत हुआ।बता दे सरस्वती साहू 5 सितम्बर 2001 से प्राथमिक शाला सिंघौरी में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे।ततपश्चात उन्हें 8 सितम्बर 2008 को मिडिल स्कूल सिंघौरी में उच्च वर्ग शिक्षक के रूप में प्रमोशन मिला।जो आज पर्यन्त तक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। संयुक्त संचालक दुर्ग के आदेशानुसार उन्हें प्रधान पाठक के रूप में पुनः सिंघौरी स्कूल पदांकन किया गया।इस प्रकार सरस्वती साहू विगत 25 वर्षो से सिंघौरी स्कूल में अपनी शिक्षकीय सेवाएं दे रही है। प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत होने के पश्चात सरस्वती साहु ने बताया कि मेरे 25 वर्षो की शिक्षकीय कार्यो पर सिंघौरीवाशियों का अपार प्रेम और सहयोग मिला।संस्था की ओर से धनीराम बंजारे संकुल समन्वयक सहित रामगोपाल चंद्राकर, शशिकला यादव,प्रतिभा, देवेंद्र साहू,नुतेश्वर चंद्राकर,सरिता बंजारे, प्रशांत बघेल,पूनम साहू,राजेश गायकवाड़, किरण खरे एंव साजन वर्मा ने बधाई दी।

नालसा योजनाओं एवं विधिक सहायता की जानकारी

लईवलीहुड कॉलेज चोरभट्टी में 'मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0' विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

बेमेतरा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास के मार्गदर्शन तथा श्रीमती अनिता कोशिमा रावटे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के निर्देशन में लईवलीहुड कॉलेज चोरभट्टी में ''मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0'' विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन एवं विद्यार्थियों को मध्यस्थता की प्रक्रिया, उसके लाभ तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना था।

मध्यस्थता की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी

शिविर में अधिकार मित्र पंकज घृतलहरे, धरमू बारले एवं तरूण आनंद द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि मध्यस्थता न्यायालयीन प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है। इसमें एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर उन्हें आपसी सहमति से समाधान तक पहुँचने में सहयोग करता है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया लचीली, सरल एवं कानूनी जटिलताओं से मुक्त होती है, जिससे आपसी मतभेद कम होते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान संभव होता है।अधिकार मित्रों ने बताया कि मध्यस्थता से बहोत से लाभ प्राप्त होते हैं जैसे रिश्तों में आई दरार को सुधारने और संबंधों को पुनः स्थापित करने का अवसर मिलता है। पक्ष स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हिंसा, घृणा एवं तनाव से दूर रहकर सभ्य एवं संवादात्मक समाधान संभव होता है।ह प्रक्रिया मुकदमे का विचारण नहीं करती और न ही गुण-दोष पर निर्णय देती है। न्यायिक प्रक्रिया की तुलना में यह कम खर्चीली है। सफलता की संभावना अधिक होती है तथा यह दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। कुछ घंटों या दिनों में समाधान संभव है, जिससे समय की बचत होती है। समझौते से मानसिक शांति प्राप्त होती है। मध्यस्थता से निराकृत प्रकरणों में न्याय शुल्क की छूट भी प्रदान की जाती है। शिविर में बताया गया कि मध्यस्थता के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के विवादों का समाधान संभव है दुर्घटना दावा प्रकरण, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस प्रकरण, वाणिज्यिक विवाद, सर्विस मैटर, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली प्रकरण, विभाजन एवं बेदखली संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण प्रकरण।

नालसा योजनाओं एवं विधिक सहायता की जानकारी

कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (द्धरू) की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। नालसा टोल फ्री नंबर 15100 एवं सालसा मोबाइल नंबर 9340062331 के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की जानकारी साझा की गई। साथ ही पॉक्सो अधिनियम 2012, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता, आशा अभियान 2025 के अंतर्गत बाल विवाह को अपराध के रूप में रोकथाम, तथा साइबर अपराध में डिजिटल अरेस्ट एवं मनी म्यूल्स से संबंधित सावधानियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों एवं उपस्थित नागरिकों में विधिक जागरूकता बढ़ाने तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का संदेश दिया गया।

परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के निर्देशानुसार हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 20 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से 12:15 बजे तक जिले के 77 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय एवं महाविद्यालयीन परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2026 में प्रस्तावित हैं।परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 12 फरवरी से 31 मई 2026 तक बेमेतरा जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, अनावश्यक कोलाहल एवं मोटरयान के विद्युत हार्न के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी, जबकि रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति से धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। आदेश जारी होते ही प्रभावशील होगा तथा इसकी सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित एवं प्रकाशित की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में एसआईआर के तहत 27 लाख नाम कटे, जुड़वाने के लिए आए सिर्फ 2.75 लाख आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है. इसके तहत 21 फरवरी को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा वोटर्स कम हो जाएंगे। इसकी बड़ी वजह है कि जिन लोगों के नाम शिफ्टिंग, त्रुटि या एसआईआर फार्म नहीं भरने के कारण कटे हैं, उनमें से अधिकांश लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन ही नहीं किया है। एसआईआर के ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद प्रदेश में 27.34 लाख लोगों के नाम कट गए थे। इनमें से मात्र 2.75 लाख लोगों ने ही नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। प्रदेश में एसआर्दआर के पहले 2.12 करोड़ वोटर्स थे। 23 दिसंबर को प्रारंभिक प्रकाशन के बाद करीब 13 फीसदी लोगों के नाम कट गए। इसके बाद नाम जुड़वाने, संशोधन और छूटे हुए लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने शुरू की। जानकारी के मुताबिक, सिर्फ पौने तीन लाख लोगों ने फार्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के आवेदन किए हैं। यह कटे हुए 27 लाख नामों का 10 फीसदी हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 27.34 लाख में से 6.42 लाख नाम मृत्यु के कारण कटे हैं। कुछ नाम त्रुटिवश कटे हों, वे ही जुड़ सकते हैं. शेष 19.13 लाख नाम शिफ्टिंग या अन्य वजहों से कटे हैं। 1.79 लाख नाम डबल एंट्री के कारण कटे हैं। यानी दोहरा नाम होने के कारण एक नाम जुड़े रहेंगे और दूसरा नाम काट दिए गए हैं। 21 फरवरी को जारी होने वाले अंतिम सूची में प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 1.90 करोड़ के आसपास होने की संभावना है. स्क्रूक्के पहले यह संख्या 2.12 करोड़ से अधिक थी. एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम छोटी-छोटी त्रुटियों जैसे उपनाम हटने, दो नाम एक साथ जुड़ने जैसी एआई द्वारा पकड़ी गई गलतियों के कारण भी हटे हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाली और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और जैव विविधता का संरक्षण करना है। इसके माध्यम से वायु की गुणवत्ता सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना और सतत विकास के द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ व संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना है। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से वन विकास निगम एवं एनएमडीसी बचेली के बीच विगत 13 जनवरी को 50 हजार पौधों के रोपण हेतु अनुबंध हुआ है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन को मजबूत करना तथा स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है। वन विकास निगम वर्ष 2005 से एनएमडीसी के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पौधारोपण कार्य कर रहा है। अब तक निगम द्वारा कुल 15 लाख 37 हजार पौधों का रोपण किया जा चुका है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है और क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विस्तार हुआ है। यह पौधारोपण कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसमें स्थानीय प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा पौधों की देखरेख और संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रूप से विकसित हो सकें। गौरतलब है कि इस अभियान के लिए वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विकास निगम की सराहना की है। उनका मानना है कि इस अभियान से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पौधरोपण, देखरेख और संरक्षण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी से ग्रामीणों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। एनएमडीसी बचेली द्वारा यह पहल कंपनी की सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के अंतर्गत की जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय विकास और आजीविका सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मां से बिछड़कर खेत में पहुंचा चार माह का तेंदुए का शावक

रायपुर। गौरतलब है कि श्रृंगी ऋषि पहाड़ी की तराई में स्थित खेतों में ग्रामीणों ने लगभग चार माह के तेंदुए के शावक को देखा। संभावना है कि शावक अपनी मां से बिछड़कर भटकते हुए रिहायशी क्षेत्र तक पहुंच गया था। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से शावक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में वन विभाग ने एक और सराहनीय कार्य किया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के दिशा-निर्देशों में धमतरी जिले के नगरी-सिहावा क्षेत्र अंतर्गत बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के ग्राम छिपली पारा में तेंदुए के एक शावक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद विभागीय प्रक्रिया के तहत शावक को नगरी स्थित पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पशु चिकित्सकों द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच में शावक पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। रेंज अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार शावक को आगे की देखभाल और सुरक्षित वातावरण के लिए नया रायपुर स्थित जंगल सफारी भेजा गया है। नगरी-सिहावा क्षेत्र सघन वनों और पहाड़ी भू-भाग के कारण तेंदुए और अन्य वन्यजीवों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास माना जाता है। वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी मदद मिल रही है।

उप अभियंता भर्ती विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा की वर्ष 2011 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें 66 उप अभियंताओं (सिविल) की नियुक्तियां नियमों के विपरीत बताते हुए निरस्त कर दी गई थीं। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल शामिल थे, ने 3 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए इन नियुक्तियों को अवैध घोषित किया था। अदालत ने कहा था कि भर्ती विज्ञापन के मुताबिक अभ्यर्थियों के पास निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी था, जबकि कई चयनित उम्मीदवारों ने डिग्री या डिप्लोमा बाद में हासिल किया। कोर्ट ने यह भी माना कि 275 पदों के लिए जारी विज्ञापन से अधिक नियुक्तियां की गईं, जो सेवा नियमों के अनुरूप नहीं था। सुनवाई के दौरान चयनित उप अभियंताओं की ओर से यह दलील दी गई थी।

श्रममंत्री देवांगन ने ली श्रम विभाग की मैराथन समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

श्रममंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन,श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष फोकस

- श्रमिकों की हितों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें कमी मिलने पर संबंधित उद्योग को निर्देशित करें

रायपुर/ संवाददाता

श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज गुरुवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में श्रम विभाग की दो चरणों में मैराथन समीक्षा बैठक ली। प्रथम चरण की बैठक में श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों की योजनाओं और कारखानों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए की कारखाने की नियमित तौर पर निरीक्षण करें। श्रमिकों की हितों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। कमी मिलने पर संबंधित उद्योग को निर्देशित करें। हर महीने किए जाने वाले निरीक्षण की भी समीक्षा करने की निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, उनके हितों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप श्रमिक भाई बहनों को योजनाओं के ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाए, सुरक्षा के मानको का पूरा ख्याल रखने का प्रयास करें। श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, और योजनाओ का क्रियान्वयन समय अवधि में पूर्ण करें। बैठक में श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, उप सचिव श्री विपुल गुप्ता, अपर श्रमायुक्त एस. एल. जांगड़े, श्रीमती सविता मिश्रा, बीओसी सचिव गिरीश रामटेके सहित जिलो से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक अधिनियम को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ईएसआईसी और पीएफ का लाभ सुनिश्चित करने साथ ही श्रमिकों की संख्या का मिलान करने के भी निर्देश दिए गए। ठेकेदार को जितने श्रमिकों का लाइसेंस प्राप्त है, उतने ही श्रमिक कार्यरत है की नहीं यह सुनिश्चित करने कहा गया। इसके साथ-साथ निजी कंपनियों से सेवानिवृत हो चुके कर्मियों के उपादन भुगतान संबंधी मामले के जल्द निराकरण, विभिन्न माध्यमों से आने वाले शिकायतों का समय अवधि में निराकरण, करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत किफायती दर पर भोजन केंद्र की भी समीक्षा की गई। प्रदेश के साथ जिलों में जल्द ही श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ करने निर्देश दिए गए। इनमें मुंगेली, सक्ति, जगदलपुर, कांकेर, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जशपुर और जगदलपुर में केंद्र शुरू करने कहा गया है। दूसरे चरण की बैठक में मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं और औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने सभी जिलों के डिस्पेंसरी की समीक्षा की। ओपीडी की संख्या को और बढ़ाने और श्रमिकों के गुणवत्तापूर्ण इलाज के निर्देश दिए गए। डिस्पेंसरी के स्टाफकी रोजाना हाजिरी बायोमेट्रिक के आधार पर करने के निर्देश दिए। प्रमुख डिस्पेंसरी में सुविधा और बढ़ाने कार्य योजना बनाने कहां गया है। मंत्री श्री देवांगन ने उद्योगों में नजदीकी डिस्पेंसरी का पता चस्पा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

राजिम कुंभ कल्प 2026 में आस्था और अध्यात्म का विराट संगम-अरुण साव....

- विराट संत समागम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महामंडलेश्वर और साधु-संतों से लिया आशीर्वाद

रायपुर/ संवाददाता

राजिम कुंभ कल्प 2026 मेला में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विराट संत समागम में पधारे साधु-संतों एवं महामंडलेश्वरों से आर्शीवाद लिया। इस विराट संत समागम को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि, राजिम कुंभ कल्प आस्था, अध्यात्म और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम बन गया है। त्रिवेणी संगम की यह पावन भूमि सदियों से साधु, संतों और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती रही है। कुंभ कल्प मेला सनातन संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है, जो समाज को धर्म, सद्भाव और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री साव ने कहा कि, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राजिम कुंभ कल्प का पुनः भव्य आयोजन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इस आयोजन से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। राजिम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और अध्यात्म की जीवंत पहचान है। देश-विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन यह दर्शाता है कि राजिम

कुंभ कल्प अब वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि साधु-संतों और महामंडलेश्वरों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के लिए अमूल्य धरोहर है। संतों के मार्गदर्शन से प्रदेश शांति, समृद्धि और कल्याण के पथ पर आगे बढ़ेगा। मंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि संत समागम और कुंभ कल्प मेला समाज में सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ एक आदर्श और कल्याणकारी राज्य के रूप में नई ऊंचाइयों को छुएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजिम कुंभ कल्प के पावन अवसर पर भगवान श्री राजीव लोचन जी एवं राजिम भक्तिन माता की पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान श्री राजीव लोचन जी से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर महामंडलेश्वर विशोकानंद भारती जी महाराज, मंत्री राजेश अग्रवाल जी, विधायक रोहित साहू जी, नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप जी, नगर पंचायत अध्यक्ष महेश यादव जी, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धुएँ से मिली मुक्ति,समय की हो रही बचत

- 01 लाख 22 हजार 545 से अधिक हितग्राहियों को प्रदान किए गए गैस कनेक्शन

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शन से महिलाओं को धुएं से मुक्ति तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आधार आ रहा है। मुंगेली जिले की अनेक महिलाओं को रसोई में लकड़ी और उपलों के धुएँ से भरी, आँखों में जलन और साँसों में तकलीफ़ सहित अनेक समस्याएं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ने इस तस्वीर को बदल दिया है। आज वही रसोई स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मान से भरी हुई है। जिले में 01 लाख 22 हजार 545 से अधिक हितग्राहियों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। नगर पंचायत सरगांव की श्रीमती रंजित वर्मा ने बताया कि वे पहले लकड़ी और कंडे से खाना बनाती थीं। घर के भीतर धुएँ का भारी गुबार भर जाता था, जिससे आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती थीं। साथ ही, लकड़ी इकट्ठा करने और चूल्हे पर खाना पकाने में अत्यधिक समय लग जाता था, जिससे समय पर भोजन भी नहीं बन पाता था। अब गैस कनेक्शन मिलने के बाद उनके घर में धुएँ से पूरी तरह राहत मिल गई है। समय की बचत हो रही है और परिवार को समय पर स्वच्छ व सुरक्षित भोजन मिल पा रहा है। पांच सदस्यीय परिवार की गृहिणी रंजिता वर्मा ने इस योजना को अपने जीवन के लिए वरदान बताया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

नक्सलवाद खात्मे को लेकर

गृहमंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग तारीख बता रहे है कौन सा सही है.....

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सलवाद खात्मे की तिथि 31 दिसम्बर 2026 बताये जाने पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा नक्सलवाद खात्मे को लेकर क्या केंद्रीय गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री के बीच मतभेद है? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नक्सलवाद खात्मे की डेड लाईन 31 मार्च 2026 बताते है, वही गृहमंत्री के साथ बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री मीडिया के सवालो का जवाब देते हुए कहते है, 31 दिसम्बर 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। आखिर क्या चल रहा

है? इन दोनों प्रमुखों के बयान से जनता भ्रमित है।सच क्या है? जनता जाना चाहती है। जनता केंद्रीय गृहमंत्री के बयान पर भरोसा करें या राज्य के मुखिया पर?प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा पूरा प्रदेश चाहता है कि नक्सलवाद खत्म हो।इसकी ठोस रणनीति बने ताकि भविष्य में इस प्रकार से हिंसात्मक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगे। फोर्स और सुरक्षा के जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही कर रहे है। लेकिन गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान का विरोधभास संसय पैदा कर रहा है। क्या केंद्रीय गृहमंत्री हड़बड़ी में है, इसलिये 31 मार्च की बात कर रहे है और मुख्यमंत्री वास्तविकता को जान रहे है, इसलिये 31 दिसम्बर 2026 तक कि डेड लाईन बता रहे है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा नक्सलवाद खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री को स्पस्ट जवाब जनता को देना चाहिए।

अवैध शराब परिवहन करते एक आरोपी पकड़ाया

रायपुर। जिले की चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 42 पौवा देशी प्लेन शराब जब्त किया है। मामले में आरोपी के विरूध्द 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा जिले में अवैध शराब परिवहन व बिक्री में अंकुश लगाने सक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भापुसे) के पर्यवेक्षण मे कार्यवाही किया जा रहा है।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की पत्रकार वार्ता

अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 16 नवीन शाखाएं खोली

रायपुर/ संवाददाता

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वर्ष 2025-26 में कृषि ऋण वितरण हेतु 9 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 7 हजार 667 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। ऋण प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या 15. लाख 55 हजार है। खरीफसीजन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख 04 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी समितियों के माध्यम से की गई। किसानों को धान खरीदी की राषि 31 हजार 275 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। सहकारिता मंत्री बताया कि सहकार से समृद्धि के अंतर्गत 515 नई पैक्स समितियों का गठन किया जा चुका है, साथ ही 351 डेयरी सोसायटी, 322 फिशरीज सोसायटी, 153 वनोपज सोसायटी सहित कुल 1341 सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। राज्य के 2058 पैक्स समितियों में से 2028 समितियों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है। राज्य में 2058 पैक्स समितियों में माईक्रो ए.टी.एम. लगाए जा चुके हैं, जिनसे 230 करोड़ रूपये का ट्रान्जेक्शन हो चुका है। पैक्स के सामान डेयरी समितियों में भी माईक्रो ए.टी.एम. उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विगत 2 वर्ष में अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की 16 नवीन शाखाएं खोली गई है। वर्तमान में 345 शाखाएं कार्यरत हैं। सहकारी बैंको में ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ब्रांच स्तर पर 169 नवीन ए.टी.एम. मशीन भी लगाये गये हैं। राज्य में सहकारिता क्षेत्र अंतर्गत 04 सहकारी शक्कर कारखाने कार्यरत हैं, जिनसे 55 हजार से अधिक गन्ना उत्पादक किसान जुड़े हुए हैं। वर्ष 2024-25 में 6.92 लाख मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी एवं 67 हजार मीट्रिक टन शक्कर का उत्पादन किया गया है। गन्ना विक्रेता किसानों को 290 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। छ.ग. के शक्कर कारखानों का औसत शक्कर रिकवरी दर 11.20 प्रतिशत है, जो देश के औसत शक्कर

रिकवरी दर 9.28 प्रतिशत से काफी अधिक है। परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत प्रथम चरण में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में 100 बस चलाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत ऐसे ग्रामों को जहॉ पूर्व में बस सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे ग्रामों को जनपद मुख्यालय/नगरीय क्षेत्र/तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को जोड़ना। उन्होंने कहा कि इस हेतु राज्य शासन द्वारा प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता के रूप में प्रथम वर्ष 26 रूपए द्वितीय वर्ष 24 रूपए एवं तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से एवं मासिक कर पूर्णत: छूट अधिकतम 03 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत अब तक 69 चयनित मार्गों में 69 बसों का संचालन किया जा रहा है, उक्त बसों के संचालन से कुल 450 नए गांव तक पहली बार यात्री बस सुविधा पहुँच रही है, तथा 18 बस संचालन की कार्यवाही प्रकियाधीन है। वर्ष 2026-27 में इस योजना अंतर्गत 200 नवीन बस संचालन की कार्ययोजना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में लगभग 15 हजार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 6 हजार 700 की मृत्यु हुई है। सड़क दुर्घटना में शून्य मृत्यु जिले के रूप में पूरे भारत में 100 जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से रायपुर जिले को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। भविष्य में दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं जगदलपुर को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति अंतर्गत प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता को वाहन मूल्य का 10 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 01 लाख छूट (सब्सिडी) दी जा रही है। इस योजना अंतर्गत ई.व्ही. वाहनों के जीवनकाल कर मे 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इस निति के तहत 1 लाख 73 हजार 618 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन किया गया है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान मे 60 हजार से अधिक वाहन स्वामियों को 125 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष मे 110 करोड़ रूपए इलेक्ट्रिक सब्सिडी प्रदाय किये जाने हेतु बजट में प्रस्तावित किया गया है।

संपादकीय

मुफ्त उपहारों की राजनीति पर रोक की सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

देश में चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को रिझाने के लिए जिस तरह मुफ्त तोहफों या उपहारों की राजनीति की जा रही है, उसने एक तरह से नतीजों की शुचिता को कसौटी पर रख दिया है। भारतीय राजनीति में पिछले कई वर्षों से यह प्रवृत्ति जटिल होती गई है। हालांकि इस मसले पर सवाल भी उठे हैं और मुफ्त तोहफों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने को लोकतंत्र के लिए एक घातक चलन बताया गया है। विडंबना यह है कि लगभग सभी राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वे भी इसी तरीके को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर जो दल या गठबंधन सत्ता में होते हैं, वे वादों या घोषणाओं के साथ-साथ चुनावों के ठीक पहले कोई योजना या कार्यक्रम लागू करने के जरिए भी मतदाताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुफ्त उपहारों को भारतीय राजनीति में एक घातक प्रवृत्ति बताया है, लेकिन इस पर रोक को लेकर अब तक कोई ठोस नियमन सामने नहीं आ सका है। यही वजह है कि आज राजनीतिक दलों के बीच एक तरह की होड़ देखी जाती है कि वोट हासिल करने के लिए मतदाताओं को कौन कितना ज्यादा लाभ पहुंचाने की घोषणा करता है। नतीजतन, स्वच्छ चुनाव और विवादरहित नतीजे आज एक सदिच्छा की तरह लगने लगे हैं। राजनीतिक दलों से यह उम्मीद करना मुश्किल हो गया लगता है कि इस दिशा में वे अपनी ओर से कोई ऐसी पहल करेंगे, जो चुनावी जीत के लिए मुफ्त की रेवड़ियों के चलन पर रोक लगाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मसले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है, तो इससे एक बार फिर मुफ्त की चुनावी रेवड़ियों पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि करीब चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने केंद्र और निर्वाचन आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें चुनाव से पहले 'अतार्किक मुफ्त उपहार की घोषणा' या इसे वितरित करने वाली राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त या उसका पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। उस समय पीठ ने इसे गंभीर मुद्दा करार दिया था और कहा था कि कभी-कभी मुफ्त उपहार योजना का बजट नियमित बजट से अधिक हो जाता है। सवाल है कि अगर कोई मतदाता मुफ्त की सौगात दिए जाने के असर में किसी उम्मीदवार को वोट देता है, तो क्या यह एक तरह की सौदेबाजी नहीं कही जाएगी? अगर कोई सत्ताधारी पार्टी चुनावों के ठीक पहले किसी योजना या कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाती है, तो उसकी जीत को कितना निष्पक्ष माना जाएगा? दिनोंदिन बढ़ती मुफ्त उपहारों की राजनीति के बीच होने वाले चुनाव को किस हद तक स्वच्छ और स्वतंत्र कहा जाएगा?

ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि अमेरिका-भारत-यूरोपीय संघ यानी जी-7 प्रभुत्व वाले प्रेम त्रिकोण और भारत-रूस-चीन यानी ब्रिक्स देश वाले प्रेम त्रिकोण के बीच भारत कब, कैसे और कितना गुटनिरपेक्ष संतुलन बना पाएगा, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रख पाएगा? क्योंकि सब कुछ इन्हीं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातों-मुलाकातों पर निर्भर करेगा। दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र और पहली-चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका व भारत में पुनः प्रेम के पींगे परवान चढ़ने शुरू हो गए। तमाम अंतर्राष्ट्रीय व द्विपक्षीय विरोधाभासों के बीच पारस्परिक सहयोग के विभिन्न जटिल पहलुओं पर जो रजामंदी दिखाई गई और फिर यह तय हुआ कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है! जिसके अपने वैश्विक निहितार्थ हैं। शायद इसी हद पर वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवंतु सुखिनः की गारंटी निर्भर है।

ट्रंप-मोदी के आपसी रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के द्विपक्षीय व वैश्विक मायने

(कमलेश पांडे)

ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि अमेरिका-भारत-यूरोपीय संघ यानी जी-7 प्रभुत्व वाले प्रेम त्रिकोण और भारत-रूस-चीन यानी ब्रिक्स देश वाले प्रेम त्रिकोण के बीच भारत कब, कैसे और कितना गुटनिरपेक्ष संतुलन बना पाएगा, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रख पाएगा? क्योंकि सब कुछ इन्हीं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातों-मुलाकातों पर निर्भर करेगा।

इसलिए कूटनीतिक हल्के में इस बात की आशंका अभी से ही जताई जा रही है कि आखिर अमेरिका कब तक अपने इस परिवर्तित स्टैंड पर कायम रहा पाएगा? क्या भारत को हांकने या फंसाने की उसकी फितरत बदल पाएगी? और यदि नहीं तो फिर नए भारत की उस पर क्या सधी प्रतिक्रिया होगी? जैसा कि भारत ने रणनीतिक ट्रेलर अमेरिका को दिखा भी दिया है जिसकी वजह से बिगड़ैल ट्रंफ 9 महीने बाद ही सही पर पुनः काबू में आए हैं। ऐसा इसलिए कि भारत के पास द्विपक्षीय विकल्पों की कमी नहीं है!

इस प्रकार देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच के संबंध जो साल 2025 की गर्मियों में व्यापारिक तनाव, रूस से भारत के भरोसेमंद संबंधों और टैरिफ पर टैरिफ युद्ध के कारण ठंडे पड़ गए थे, अब फरवरी 2026 आते आते गर्म होने लगे हैं। अब इनके बीच का वासंतिक प्रेम पुनः जाग गया है और आर्थिक रुमानियत और रणनीतिक अठखेल पुनः परवान चढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं।

जहां तक मोदी-ट्रंफ के बीच के तनाव के मुख्य कारणों की बात है तो 2025 में ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 50त्न तक टैरिफ बढ़ा दिए, खासकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और जेम्स पर, जिससे द्विपक्षीय व्यापार वार्ता रुक गई। समझा जाता है कि भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना अमेरिका को पसंद नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का नरम रुख भी विवादास्पद रहा। वहीं, चुनावी राजनीति और अमेरिका फर्स्ट नीति ने व्यक्तिगत रसायन को प्रभावित किया।

और अब जब मोदी-ट्रंप के आपसी रिश्ते पर जमी बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया की बात हुई तो बताया गया कि ट्रंप ने सितंबर 2025 में ही मोदी की तारीफ की और रिश्तों को खास बताया, जिसका मोदी ने सोशल मीडिया पर जवाब भी दिया। भारत की चुप्पी कूटनीति और एससीओ (एससीओ) जैसे मंचों पर मजबूत स्थिति और भारत-यूरोपीय संघ (ईयू)

ट्रेड डील ने अमेरिका को भारत की अहमियत समझाई। लिहाजा, फरवरी 2026 में ही ट्रंप की मोदी से फोन कॉल ने जमी बर्फ को पूरी तरह पिघला दिया, जिससे ट्रेड डील की राह आसान हुई।

कहना न होगा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में टैरिफ विवाद फरवरी 2026 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन वार्ता से सुलझा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया, जबकि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने और अमेरिकी उत्पादों पर जीरो टैरिफ का वादा किया। इस समझौते की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं- ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि मोदी के अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से रेसिप्रोकल टैरिफ कम किया गया। रूस से तेल आयात रोकना, अमेरिका/वेनेजुएला से अधिक खरीद, और नॉन-टैरिफ बैरियर्स हटाना प्रमुख रियायतें रहीं। कुल टैरिफ 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया, जिसमें रूसी तेल से जुड़ा 25 प्रतिशत दंड समाप्त हुआ।

जहां तक इनको सुलझाने की प्रक्रिया की बात है तो बेहद लंबी वार्ताओं के बाद (अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक) फोन कॉल ने अंतिम मुहर लगाई। भारत ने कृषि, डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र बचाए, जबकि अमेरिका को व्यापार घाटा कम करने का लाभ मिला। यह द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का रास्ता साफ करता है।

इस प्रकार ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ (खासकर रूसी तेल खरीदने के कारण) अब पूरी तरह हटाए लिए गए हैं, क्योंकि हालिया टेलीफोनिक वार्ताओं से सकारात्मक प्रगति हुई है। सितंबर 2025 में भारत-अमेरिका के बीच 7 घंटे की बैठक के बाद चर्चाएं तेज हुई, जहां 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ हटाने पर सहमति बनी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने कहा कि 8-10 हफ्तों में विवाद सुलझ सकता है, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ भी घटेंगे।

इसलिए फरवरी 2026 तक ट्रंप-मोदी फोन कॉल ने गति दी, लेकिन पूर्ण समाधान एससीओ जैसे मंचों पर निर्भर है। फिर भी चुनौतियां अभी बाकी हैं। 50त्न टैरिफ स्टील, एल्यूमीनियम, टेक्सटाइल पर अभी प्रभावी हैं, हालांकि निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। अमेरिकी सांसदों ने इन्हें खत्म करने की मांग की, लेकिन ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति बाधा बनी हुई है।

इस प्रकार भारत अमेरिका डील के द्विपक्षीय मायने स्पष्ट हैं। भारत और अमेरिका के बीच हालिया डीलें, विशेष रूप से रक्षा और व्यापार समझौते, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं। ये डीलें रणनीतिक साझेदारी को गहरा करती हैं, भले ही टैरिफ जैसे विवाद बने रहें। खासकर रक्षा समझौते का अपना महत्व हैं। भारत-अमेरिका ने 10 साल के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 2015 की रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, सूचना साझाकरण और हिंद-प्रशांत में चुनौतियों (जैसे चीन का प्रभाव) का सामना करने के लिए आधारशिला बनेगा। टैरिफ तनाव के बावजूद रक्षा सहयोग बढ़ रहा है।

जहां तक व्यापार डील की प्रगति की बात है तो दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें हाल ही में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया। जबकि, दूध, कृषि और डेटा स्थानीयकरण जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ और जीएसपी लाभ बहाली चुनौतियां बनी हुई हैं। पहला चरण सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा करने की कोशिश थी।

इन बातों का द्विपक्षीय प्रभाव यह पड़ेगा कि ये डीलें आर्थिक निर्यात बढ़ावा, रोजगार सृजन और रक्षा तकनीक हस्तांतरण लाएंगी। भू-राजनीतिक

डॉ दर्शनी प्रिय की पुस्तक को उपसभापति हरिवंश ने किया लोकार्पित

'प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न' पुस्तक का हुआ भव्य लोकार्पण

(आशीष नेमा)

नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी चेयरमैन हॉल में एक महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 'प्रधानमंत्री मोदी के अनमोल रत्न' पुस्तक का अनावरण किया गया। देश की जानी-मानी लेखिका और पत्रकार डॉ. दर्शनी प्रिय द्वारा लिखी गई यह पुस्तक 35 असाधारण पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं के जीवन की गहराई से पड़ताल करती है, जिनकी जीवंत कहानियाँ 'नए भारत' की संवेदनात्मक भावना को दर्शाती हैं। अगली पीढ़ी को एक विरासत के रूप में थाती प्रदान करती इस पुस्तक के सामाजिक निहितार्थ है। डॉ दर्शनी की एक लेखिका के तौर पर इसमें खास मेहनत दिखती है।उनके प्रयास से असली जननायकों को हम जान रहें तो वे अंधेरी गलियों में गुमनाम हो जाते। इस समारोह में राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहबाज हुसैन सहित राज्यसभा की सांसद सुशीला गुप्त भी उपस्थिति रही। अतिथियों ने पद्म सम्मान प्रणाली में हुए परिवर्तनकारी बदलाव पर प्रकाश डाला, जो विशेषाधिकार के बजाय योग्यता और जमीनी स्तर पर प्रभाव को प्राथमिकता देने वाले 'पीपल पद्म' की ओर बढ़ रहे है।' कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पद्म श्री पुरस्कार विजेता विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं :पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में मौजूद रही। कला के क्षेत्र में एक जानी-मानी हस्ती, जो भारतीय लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती हैं।पद्म श्री पुरस्कारों का महत्व

हाल के दिनों में सत्ता की सार्थक पैरोकारी से बढ़ा है।पद्म श्री भारत गणराज्य का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में अपनी स्थापना के बाद से, यह कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में 'विशिष्ट सेवा' का प्रतीक बन गया है।

वर्तमान प्रशासन के तहत, चयन प्रक्रिया में एक बड़ा श्बदलाव आया है : अब जमीनी स्तर पर 'अनाम नायकों' पर जोर दिया जाता है – देश के दूरदराज के कोनों में काम करने वाले व्यक्ति जिनके योगदान पर ऐतिहासिक रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।

जन-भागीदारी : नामांकन प्रक्रिया अब जनता के लिए खुली है, जिससे यह वास्तव में एक लोकतांत्रिक 'जन आंदोलन' बन गया है।

समग्र प्रभाव : पेशेवर उत्कृष्टता से परे, समिति एक 'सार्वजनिक सेवा के तत्व' की तलाश करती है जिसने लोगों के जीवन को छुआ हो और सामुदायिक लचीलापन बनाया हो। किताब के बारे में 'प्रधान मंत्री मोदी के अनमोल रत्न' उन लोगों को एक जीवनी के रूप में श्रद्धांजलि है जिन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। डॉ. दर्शनी प्रिय का काम देश के इन 'रत्नों' के साहस, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा को दिखाता है, जो पाठकों को भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने वाली विविध प्रतिभाओं की झलक देता है।ये पुरस्कार विजेता सिर्फ़ पदक पाने वाले नहीं हैं; वे भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा के जीते-जागते प्रतीक हैं। यह किताब उनकी प्रेरणादायक यात्राओं को हर घर तक पहुँचाने का एक प्रयास है।

त्वरित विकास को समर्पित कल्याणकारी केन्द्रीय बजट

-डॉ. महेन्द्र सिंह

पूँजीगत खर्च के जरिये अवस्थापना क्षेत्र के विकास ने विकास को तेज करने और रोजगार को बढ़ाने में उल्लेखनीय तौर पर योगदान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास में धमनियों का कार्य करता है। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार द्वारा किया गया निवेश लगातार विकास का इंजन बना हुआ है। एक ओर जहाँ केन्द्र सरकार स्वयं पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है; वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों को भी अनुदान व ऋण देकर उनके पूँजीगत खर्च को बढ़ाने में मदद कर रही है। वर्ष 2025-26 की तुलना में 2026-27 के बजट में पूँजीगत आवंटन में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए संसद में पेश किया गया गया बजट देश के त्वरित विकास को समर्पित कल्याणकारी बजट है। इस बजट में समाहित प्रस्तावों में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने और उसे निरन्तर बनाये रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही, लोककल्याण के लिए बजट प्रस्तावों पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में तीन कर्तव्यों को उजागर किया। ये हैं : (?) अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन में वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे बनाये रखना; (द्वद्व) जन आकाँक्षाओं की पूर्ति और उनकी क्षमताओं का वर्द्धन करना एवं (द्वद्वद्व) देश के प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग तक संसाधनों, सुविधाओं तथा अवसरों की पहुंच को सुनिश्चित करना। इस तरह ये कर्तव्य मोदी सरकार की सर्वसमावेशी एवं पोषणीय विकास की रणनीति को सुस्पष्ट रूप में परिभाषित करते हैं। ध्यातव्य है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के केन्द्र में एक ओर आर्थिक संवृद्धि की गति को तेज करना रहा है वहीं दूसरी तरफ सापेक्षतया वंचित लोगों एवं क्षेत्रों को उनकी क्षमता व सामर्थ्य को बढ़ाते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना रहा है। इस दृष्टि से यह कहना समीचीन है कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' का ध्येय वाक्य लोकनीतियों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन का नाभिकेन्द्र रहा है। इसमें आर्थिक समृद्धि एवं लोककल्याण में वृद्धि स्वतः विहित रहे हैं।

मोदी सरकार द्वारा संरचनात्मक आर्थिक सुधारों का मूल विचार 'रिफार्म, परफार्म व ट्रॉन्सफार्म' रहा है। इस बजट में भी, बजट प्रावधानों को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सुधारों के क्रम को जारी रखा गया है। 'विकसित भारत' के महालक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बजट में कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र, एमएसएमई, ओडीओपी, रिन्यूबल व न्यूक्लियर एनर्जी, सेमिकंडक्टर, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, जलमार्ग व रेल विकास, डिकार्बनाइजेशन, निर्यात संवर्द्धन, रक्षा क्षेत्र इत्यादि संभावनापूर्ण क्षेत्रों एवं तत्सम्बन्धी क्रियाओं के संवर्द्धन व विकास के लिए वित्तमंत्री द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित आवंटन किए गये हैं। साथ ही, मानव पूँजी के निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा और दिव्यांग सशक्तिकरण पर पर्याप्त बल दिया गया है। वस्तुतः, मानव पूँजी के बेहतर विकास से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा जनकल्याण में वृद्धि होगी।

वित्तमंत्री ने इस बजट में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को जारी रखते हुए इस पर विशेष बल दिया है। हाल के वर्षों में जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा में निरन्तर गिरावट से इस बात की पुष्टि होती है कि मोदी सरकार का राजकोषीय प्रबन्धन सम्बन्धी निष्पादन श्लाघनीय रहा है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7 प्रतिशत; 2022-24 में 6.5 प्रतिशत 2023-24 में 5.5 प्रतिशत; 2024-25 में 4.8 प्रतिशत एवं 2025-26 में 4.4 प्रतिशत था। इसे 2026-27 के बजट में कम करके 4.3 प्रतिशत पर रख गया है। ये प्रवृत्तियाँ राजकोषीय व्यवस्था की मजबूती की परिचायक हैं।

मोदी सरकार की राजकोषीय प्रवीणता एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा निरन्तर घटा है। साथ ही, वित्तमंत्री इस बात में भी सफल रही हैं कि उन्होंने इस बजट में जीडीपी के सापेक्ष केन्द्र सरकार के ऋण को 55.6 प्रतिशत पर रखा है। यह वर्ष 2025-26 के लिए 56.1 प्रतिशत रखा गया था। साथ ही, इस बजट में जीडीपी के सापेक्ष राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा में भी कमी आई है। घटते घाटे एवं ऋण से निजी पूँजी निवेश में वृद्धि होगी।

इस बजट में, राजस्व में सतत वृद्धि; पूँजीगत व्यय में वृद्धि और राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार के संकेतकों से भी देश की राजकोषीय सुदृढ़ता की पुष्टि होती है। पूँजीगत खर्च के जरिये अवस्थापना क्षेत्र के विकास ने विकास को तेज करने और रोजगार को बढ़ाने में उल्लेखनीय तौर पर योगदान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास में धमनियों का कार्य करता है। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार द्वारा किया गया निवेश लगातार विकास का इंजन बना हुआ है। एक ओर जहाँ केन्द्र सरकार स्वयं पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है; वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों को भी अनुदान व ऋण देकर उनके पूँजीगत खर्च को बढ़ाने में मदद कर रही है। वर्ष 2025-26 की तुलना में 2026-27 के बजट में पूँजीगत आवंटन में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि को भी जोड़ लिया जाय तब प्रभावी पूँजीगत व्यय की वृद्धि 22 प्रतिशत बैठती है। इस तरह मोदी सरकार की यह विचारणा सुस्पष्ट होती है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती आर्थिक उन्नति का मूलाधार है। इस बजट में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों क्षेत्रों में पूँजीगत व्यय की वृद्धि दरें इस तरह हैं: टेलीकॉम 97 प्रतिशत; रक्षा 18 प्रतिशत; रेलवे 10 प्रतिशत; सड़क व हाईवे 8 प्रतिशत एवं आवास व नगरीय विकास 6 प्रतिशत। यह तथ्य यह भी दर्शाते हैं कि बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन से अब विकासगामी क्रियाओं के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।

जीडीपी के सापेक्ष सरकारी ऋण भार को घटाकर 2030-31 तक 50 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। स्पष्ट है कि इससे आगामी वर्षों में अवस्थापना के विकास के लिए और अधिक 'फिस्कल स्पेस' मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि पूँजीगत व्यय में मोदी सरकार द्वारा की गई वृद्धि से आय में तो कई गुना वृद्धि होती ही है, इससे रोजगार में भी उल्लेखनीय तौर पर वृद्धि होती है। इस बजट में छोटे, मझोले एवं धार्मिक नगरों के विकास के लिए भी प्रावधान किए गये हैं। नगरीय क्षेत्रों में जन सुविधाओं के बेहतर विकास से जनजीवन सुगम व स्वस्थ होगा। साथ ही, इसके विकास से कारोबार सुगम होगा, इसमें वृद्धि होगी। धार्मिक व साँस्कृतिक स्थलों के उन्नयन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा देश-विदेश से पर्यटकों की आवाजाही से आर्थिकी सशक्त होगी। इस बजट में हास्पिटेलिटी तथा हेल्थ टूरिज्म से भी लोगों की आजीविका के स्रोतों में वृद्धि, रेल एवं जलमार्गों के विकास एवं अपग्रेडेशन से लाजिस्टिक्स की लागतें घटेंगी। इससे व्यापार में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था की स्पर्धात्मकता में वृद्धि से निर्यात-प्रेरित निवेश होगा।

इस बात का उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस बजट में अवस्थापना क्षेत्र के विकास के लिए 12.20 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह एक बड़ी धनराशि है। इससे विकास की गति को तेज करने तथा रोजगार को बढ़ाने में महती सहायता मिलेगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के अन्तर्गत इस बजट में 40 हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त जिन 7 रोजगारपरक क्षेत्रों को समावेशित किया गया है वे हैं: बायो फार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेन्टस, रेयर अर्थ, रसायन, पूँजीगत वस्तएँ और टेक्सटाइल्स। इनसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की संवृद्धि बढ़ेगी। वस्तुतः, ये अर्थव्यवस्था के उदीयमान क्षेत्र हैं और इनमें उत्पादन, रोजगार व निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसके अलावा बजट में लघु एवं मध्यम उद्योगों को चैंपियन बनाने के निर्णय से भी इस क्षेत्र का विकास तेज होगा। आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एमएसएमई, ओडीओपी तथा खादी क्षेत्र की भूमिका महती स्थान रखती है। रक्षा व्यय में वृद्धि; विशेष तौर पर पूँजीगत व्यय में वृद्धि से भी रक्षा मामले में हमारी आत्म-निर्भरता बढ़ेगी और रक्षा सामग्री का निर्यात बढ़ेगा।

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस बजट में जो प्रावधान किये गये हैं उनसे कृषि एवं गैर-कृषि क्रियाओं के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों को ताकत मिलेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों, युवाओं एवं महिलाओं को उद्यमी बनाने का परिणाम होगा कि स्थानीय स्तर पर आजीविका के स्रोतों का विस्तार होगा। इससे गाँवों से नगरों को होने वाला पलायन भी रुकेगा। पशु चिकित्सा के लिए बजट में की गयी व्यवस्था से पशुधन में संवर्द्धन होगा। इससे गो आधारित प्राकृतिक कृषि के विस्तार में भी सहायता मिलेगी। इस बजट को यदि समग्र रूप से देखें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि यह बजट भारत की घरेलू क्षमता का समुचित उपयोग करते हुए त्वरित आर्थिक विकास एवं लोककल्याण में वृद्धि को समर्पित है।

लेखक-भाजपा मध्यप्रदेश के प्रदेश प्रभारी व उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व मंत्री हैं।

मैदान में पसीना बहाकर गढ़ें अपना भविष्य, खेल से संवरता है चरित्र : संतराम नेताम

कोरकोटी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन , खिलाडियों में आयोजन से उत्साह

कोण्डागांव। ग्राम कोरकोटी में आयोजित दो दिवसीय डे-नाइट प्रो-कबड्डी प्रतियोगिता का समापन उत्साह और रोमांच के माहौल में हुआ। ग्राम के युवा संगठन एवं समस्त ग्रामवासियों के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता ने क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खासा उत्साह भर दिया। दूधिया रोशनी के बीच खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया।समापन समारोह को संबोधित करते हुए केशकाल के पूर्व विधायक संतराम नेताम ने कहा, ÷हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो खेल भावना के साथ अपनी योग्यता का परिचय दे। जब युवा अपनी ऊर्जा खेल के मैदान में लगाते हैं, तो वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि गलत रास्तों से भी दूर रहते हैं।÷ उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे मैदान में पसीना बहाकर अपना भविष्य गढ़ें, क्योंकि खेल से ही चरित्र का निर्माण होता है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त माध्यम हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो सफलता निश्चित है। युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाकर समाज की सुरक्षा और विकास में योगदान देना चाहिए। खेल के मैदान की चुनौतियां ही युवाओं को समर्थ और सजग बनाती हैं। पूर्व विधायक नेताम ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा बचपन से ही ईश्वर की देन होती है, जिसे निखारने के लिए मंच की आवश्यकता होती है। जब गांव के बच्चे अपने ही क्षेत्र के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखते हैं, तो वे प्रेरित होते हैं। खेल से आपसी सद्भाव बढ़ता है और पारंपरिक भारतीय खेलों को प्रोत्साहन मिलता है।

उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और वे राज्य व देश का नाम रोशन करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। रोमांचक फाइनल मुकाबले के बाद विजेता टीम को पूर्व विधायक के हाथों पुरस्कार राशि और कप प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य कपिलकांत नाग, प्रवीण अग्निहोत्री, प्रवीण बरनवाल, रिंकू पांडे, सौरभ ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज़, 28 गांवों की टीमें ले रहीं हिस्सा

बीजापुर। मिनी स्टेडियम में गुरुवार से जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। ग्रामीण युवाओं को खेल का मंच देने और उनकी प्रतिभा निखारने के मकसद से आयोजित इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में जिलेभर की टीमें दमखम दिखा रही हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य मैथ्यूज कुजूर, कलेक्टर संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे और जिला खेल अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल ने किया। उद्घाटन के दौरान स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ बड़ी संख्या में खेलप्रेमी भी मौजूद रहे, जिससे माहौल उत्साह से भरा नजर आया।

प्रतियोगिता में जिले के 28 गांवों की ग्राम पंचायत टीमें भाग ले रही हैं। आयोजकों ने विजेता टीम को 51 हजार रुपये और ट्रॉफी, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21 हजार रुपये तथा तीसरे स्थान की टीम को 11 हजार रुपये और ट्रॉफी देने की घोषणा की है। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी अलग से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की एक और खास बात यह है कि यहां से चुनी जाने वाली जिले की टॉप चार टीमें 18 से 20 फरवरी तक होने वाले ऑल इंडिया टूर्नामेंट में सीधे खेलेंगी। इससे खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। स्टेडियम में चल रहे मुकाबले खेल भावना और अनुशासन की मिसाल पेश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे आयोजन न सिर्फ युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, बल्कि जिले में खेलों के प्रति माहौल भी मजबूत करते हैं।

भामाशाह साहू सद्भाव समिति द्वारा निशुल्क स्वल्पाहार बांटा गया

नवापारा नगर । राजिम कुंभ कल्प में, गोबरा नवापारा के सक्रिय समिति भामाशाह साहू सद्भाव समिति के द्वारा कुलेश्वर मंदिर के पास में निशुल्क स्वलपाहार का आयोजन किया गया। जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने बढ़कर हिस्सा लिया अध्यक्ष मोहनलाल मानिकपन उपाध्यक्ष रोमन लाल साहू उपाध्यक्ष मानिक राम साहू कोषाध्यक्ष कोमल सिंह साहू सचिव डाक्टर रमेश कुमार सोनसायटी, टीपी साहू डेरहूराम साहू, वीरेंद्र साहू खियाराम साहू दिनेश साहू भरोसी राम साहू गुरु चरण साहू पुनारद साहू नए सहयोग कर कार्यक्रम को संपन्न किया कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने आए भक्तगण एवं मेला भ्रमण करने आए लोगों ने इसका अधिकाधिक रूप से लाभ लिया।

हिरोली में सीआरपीएफका सिविक एक्शन कार्यक्रम, 150 से अधिक ग्रामीणों को मिला लाभ

बीजापुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र हिरोली में तैनात 85वीं बटालियन सीआरपीएफ ने गुरुवार को सिविक एक्शन प्रोग्राम और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई। कमांडेंट सुनील कुमार राही के मार्गदर्शन और उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उन्हें शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में हिरोली सहित आसपास के पटेलपारा, सरपंचपारा, नुल्लीपारा, मर्रेपारा और गायतापारा के 150 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान जरूरतमंद परिवारों को दैनिक उपयोग की घरेलू सामग्री, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक सामान वितरित किए गए। साथ ही बटालियन के चिकित्साधिकारी ने चिकित्सा शिविर लगाकर बीमार ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाइयों के साथ विटामिन संबंधी टॉनिक भी प्रदान किए। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलता है। कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालित विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।कमांडेंट सुनील कुमार राही ने बताया कि बीजापुर में तैनाती के बाद से 85वीं बटालियन आम जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। समय-समय पर सामग्री वितरण और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से सुरक्षा बलों और स्थानीय जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा तथा ग्रामीण विकास गतिविधियों में अधिक भागीदारी निभाएंगे। कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी पवन कुमार, सहायक कमांडेंट काशीराव श्रीराम, हेमंत भट्ट और शुभम सिंह परिहार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार, अन्य अधिकारी व जवान, ग्राम पंचायत सचिव कमला सकोरकर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वनाग्नि से सुरक्षा हेतु वनमंडल स्तरीय कार्यशाला संपन्न

कांकेर। वन काष्ठागार सिंगारभाट में वनों को अग्नि से सुरक्षा एवं रखरखाव के उद्देश्य से वनमंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त एवं वनमंडलाधिकारी कांकेर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वनाग्नि से बचाव, त्वरित नियंत्रण एवं निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने संबंधी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है, जिससे वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम में उपवनमंडलाधिकारी कांकेर/कोरर, परिक्षेत्र अधिकारी कांकेर, सरोना, नरहरपुर, चारामा, कोरर सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। वन काष्ठागार सिंगारभाट में आयोजित वनाग्नि सुरक्षा कार्यशाला में दीप प्रज्वलित करते अधिकारीगण।

कलेक्टर ने केशकाल एवं बड़ेराजपुर विकासखंड में विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का लिया जायजा

विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के दिए निर्देश

कोण्डागांव। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने गुरुवार को केशकाल एवं बड़े राजपुर विकासखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों का सघन दौरा कर स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और छात्रावासों सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम सिंघनपुर और ग्राम तोसकापाल में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र भवन का निरीक्षण किया और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए। बड़े राजपुर विकासखंड अंतर्गत उन्होंने ग्राम गारावंडी में आंगनबाड़ी केंद्र कुम्हारपारा का निरीक्षण किया और बच्चों को दी जाने वाली पोषण आहार की जानकारी ली। साथ ही बच्चों से शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने बड़ेराजपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से संवाद कर पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और अच्छे से पढ़ाई करने हेतु प्रोत्साहित किया। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन महतारी सदन भवन का जायजा लिया और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र बड़े राजपुर का भी निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और महिला वार्ड में मरीजों से चर्चा कर उनका हाल चाल जाना। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां कंप्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने प्री मेट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावासों का भी निरीक्षण किया। विश्रामपुरी में शासकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया और पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने हेतु लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, एसडीएम सुश्री आकांक्षा नायक, जनपद पंचायत बड़े राजपुर सीईओ लखेश्वर यादव, जनपद पंचायत केशकाल सीईओ अनुराग सिन्हा, डीएमसी ईमल बघेल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 से शहरी गरीबों को मिलेगा स्थायी आशियाना : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

कोण्डागांव। नगर पालिका द्वारा अंबेडकर चौक से लेकर समनापुर मार्ग तक निर्माण होने वाले बीटी रोड व नाली निर्माण भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंचे विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण को लेकर बड़ी बात कही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंच से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजनाङ्कशहरी 2.0 शहरी क्षेत्रों में निवासरत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से वर्षों से कच्चे मकानों में रह रहे पात्र नागरिकों को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों के लिए आवास स्वीकृत होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग जिस स्थान पर काबिज हैं और वहां समेकित कर, बिजली बिल तथा संपत्ति कर जमा कर रहे हैं या जिनके पास पुराना पट्टा है लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, ऐसे सभी पात्र लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा उन्हें कब्जे का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद आवास की स्वीकृति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का लाभ उन हितग्राहियों को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2024 से पूर्व आबादी (प्रचलित/सुरक्षित) भूमि पर निवासरत हैं तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है। पात्र हितग्राहियों के चयन के लिए नगर पालिका द्वारा पात्र हितग्राही प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जिसके लिए हितग्राही को भूमि पर निवास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन परिवारों के पास देश में कहीं भी पक्का आवास उपलब्ध नहीं है, वही इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। एक परिवार को केवल एक ही आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिताउप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी।

डीएमएफ जिला होने के बावजूद दंतेवाड़ा जिला अस्पताल बदहाल

मरीजों के स्वास्थ्य अधिकारों पर कुठाराघात एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं : मनीष

अस्पताल की डायलेसिस एवं लैब यूनिट को निजि हाथों में सौंपने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण । आज भी जिला अस्पताल बना हुआ है रेफर सेंटर.

दंतेवाड़ा। हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य मिले ये उसका मौलिक एवं मानवीय अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्स माना गया है। क्षेत्र के नागरिकों एवं ग्रामीण इलाकों से आने वाले आदिवासी भाई बहनों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अधिकारों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उक्त बातें जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा के युवा मिडिया प्रभारी मनीष ठाकुर ने दंतेवाड़ा जिला अस्पताल की दिनों दिन बदहाल होती स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते कहा है। श्री ठाकुर ने भाजपा सरकार एवं दंतेवाड़ा जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य प्रशासन पर आरोप लगाते कहा है कि आज समय कहां से कहां पहुंच गया मगर हमारा दंतेवाड़ा जिला का सरकारी अस्पताल आज भी रेंफर सेंटर ही बना हुआ है। इस आधुनिक युग में जब हर चीज एडवांस होता चला जा रहा है वहीं दंतेवाड़ा जिले में आज भी दुरस्थ अंचलों से मरीजों को खाट पर ढोकर अस्पताल लाने का दृश्य दिखाई पड़ता है जो पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगाता है। स्वास्थ्य मंत्री पर कटाक्ष करते कहा कि दंतेवाड़ा से खनिज एवं न्यास निधि डीएमएफ से करोड़ों रूपए प्राप्त होने के बाद भी जिला अस्पताल बदहाल स्थिति में क्यों पड़ा हुआ है? अस्पतालों की दुदर्शा को ठीक करना छोड़ उल्टा डायलेसिस, लैब यूनिट एवं रेडियोलॉजिस्ट सेवाओं को सीआईडीएमएस के माध्यम से निजि कंपनियों को सौंपने की तैयारी अंदरखाने चल रही है जो अत्यंत ही चिंतनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे संवेदनशील विभागों का निजिकरण गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को महंगा और जटिल बना देगा। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2016-17 से डीएमएफ फंड से संचालित डायलेसिस यूनिट एवं वर्षो से संचालित जिला अस्पताल की लैब जहां विभिन्न प्रकार के जांचें निःशुल्क की जाती है उसे भी अब बेचने की तैयारी हो रही है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जिला अस्पताल में 90 परसेंट लोग ईलाज करवाने ग्रामीण इलाकों से गरीब आदिवासी तबके के लोग आते हैं। प्राईवेट अस्पतालों में महंगी इलाज वे करा नहीं सकते इसलिए सरकारी अस्पतालों में वे ईलाज के लिए आते हैं ऐसे में डायलेसिस एवं लैब यूनिट को निजि हाथों में सौंपने से संचालक मरीजों से जांच के नाम पर मनमानी रकम वसूली करेंगे। गरीब आदिवासी भाई बहन इतने रूपए कहां से दे पाएंगे। सरकार गरीब आदिवासियों की हितैषी होने का दंभ भरती है मगर असल में भाजपा की सरकार यहां के संसाधनों के साथ साथ अस्पताल की व्यवस्था को भी निजि हाथों में सौंप देना चाहती है जो बर्दाश्त के बाहर है। अगर इस प्रकार की मंशा स्वास्थ्य मंत्री ने पाल रखा है तो उसे छोड़ दे अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेगी और भाजपा का असल चाल, चरित्र व चेहरा जनता के सामने लाकर रख देगी। मिडिया प्रभारी मनिष ठाकुर ने आगे कहा कि दंतेवाड़ा जिला डीएमएफ जिला है यहां रूपयों की कोई कमी नहीं है पहले डीएमफ के राशि से अस्पताल की व्यवस्था संचालित होती थी मगर किंतु पिछले करीब 6 माह से जिला अस्पताल में डीएमएफ की राशि को रोक दिया गया है। राशि के अभाव में अस्पताल की व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। फंड नहीं दिए जाने से कई आवश्यक दवाएं एवं मेडिकल सामाग्रियों की भारी कमी हो गई है जिसका सीधा असर गरीब आदिवासी मरीजों पर पड़ रहा है। मरीजों को बाहर से महंगी दवाईयां खरीदनी पड़ रही है। अस्पताल में जांच के नाम पर भी खानापूर्ति ही की जाती है ज्यादातर जांचें लोग मजबूरी में बाहर प्राईवेट लैबों में जाकर करवाने को मजबूर होते हैं। महंगी महंगी मशीनें तो अस्पताल में लगी पड़ी है मगर मेंटनेंस एवं टेक्निशियनों के अभाव में जाचें नहीं हो रही इसका कोई लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा। थायराइड समेत कई प्रकार की जाचें आज भी लोग प्राईवेट लैब में ही जाकर करवाते हैं। डॉक्टर जो पर्ची मरीजों की लिखता है उसमें से आधी दवाईयां तो अस्पताल में मिलती ही नहीं मेडिकल से ही खरीदना पड़ता है। अब मरता क्या न करता की तर्ज पर मरीज मजबूर होकर बाहर मेडिकल से दवाईयां लेने को मजबूर होता है। यह स्थिति सरकार की संवेदनशीनता को दर्शाती है। सरकारं अगर डीएमएफ की राशि बंद नहीं करती तो अस्पताल की स्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। अंत में मिडिया प्रभारी मनीष ठाकुर ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा गरीब, आदिवासी एवं आम नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो पार्टी जनहित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

संक्षिप्त समाचार

प्रदेश सड़कों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट में न्यायमित्रों ने की शिकायत

बिलासपुर। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण सड़कों की बदहाली को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वत: संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। स्वत: संज्ञान के अलावा एक और जनहित याचिका दायर की गई है। दोनों पीआइएल की डिवीजन बेंच में एकसाथ सुनवाई चल रही है। राज्य शासन ने सड़कों की स्थिति को लेकर जवाब पेश किया। न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव व प्रतीक शर्मा ने राज्य शासन के दावों की पोल खोलते हुए सड़कों की बदहाली और अधूरे निर्माण को लेकर रिपार्ट पेश की। बीते दिवस को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई प्रारंभ हुई। राज्य शासन की ओर से दौर शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश की गई। इसमें राज्य की सड़कों के निर्माण व मेंटनेंस को लेकर जानकारी दी गई थी। प्रदेशभर की सड़कों की रिपोर्ट पेश करने और निर्माण कार्य की निगरानी के लिए हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव व अधिवक्ता प्रतीक शर्मा को न्यायमित्र बनाया है। राज्य शासन द्वारा पेश शपथ पत्र का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव व अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने डिवीजन बेंच को बताया कि वर्तमान में नए मार्गो का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में पेश किए गए शपथ पत्र और वर्तमान में पेश शपथ पत्र में कोई सारभूत अंतर नहीं है। राज्यभर में सड़कों के निर्माण व सुधार में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। लोग आज भी परेशान हैं। सड़कों की खराब स्थिति के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई है।

तोरवा पुलिस की बड़ी कार्रवाईः 10 किलो गांजा के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस के तहत थाना तोरवा और एसीसीयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 फरवरी 2026 को रेलवे स्टेशन से लगे बुधवारी बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति भारी बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला। पूछताछ के दौरान उसके जवाब संदिग्ध लगे और वह मौके से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। बैग की तलाशी लेने पर खाकी टेप से लिपटे दो अलग-अलग पैकेट मिले, जिनसे गांजा की गंध आ रही थी। जांच में कुल 10 किलो गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आमोद प्रसाद बरई उर्फ अमोद चौरसिया (28 वर्ष), निवासी मझबलिया, जिला बेतिया (बिहार) बताया। उसने खुलासा किया कि वह गांजा ओडिशा के संबलपुर से लाकर अन्य राज्यों में सप्लाई करने की फिराक में था। मामले में थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 63/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों और बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले मार्गों पर संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

ग्राम मुरली में कृषि चैपाल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने विकासखंड पाली के ग्राम मुरली में आयोजित कृषि चैपाल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फार्मर रजिस्ट्री, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एफपीओ के अंतर्गत नए किसानों को जोड़ने, ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों को प्रोत्साहित करने, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं सिंप्रकलर) के विस्तार, किसान समृद्धि योजना अंतर्गत नलकूप स्थापना, शाकम्भरी योजना के तहत पंप वितरण, कृषि यांत्रिकीकरण योजना, आगामी खरीफ मौसम हेतु दलहन, तिलहन एवं लघुधान्य फसलों के लिए क्लस्टर ग्राम चयन तथा अग्रिम खाद उठाव सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ उठाने की अपील की। चैपाल के दौरान ग्राम सरपंच द्वारा कलेक्टर श्री दुदावत का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने उपस्थित किसानों एवं महिलाओं से संवाद कर उनका हालचाल जाना तथा फसल उत्पादन, सिंचाई, समर्थन मूल्य, ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं अन्य स्थानीय मुद्दों पर सुझाव आमंत्रित किए। प्राप्त सुझावों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। महिलाओं से विशेष चर्चा करते हुए कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ के संबंध में जानकारी ली तथा योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिकता है।

छत्तीसगढ़ की पर्यावरणीय धरोहर : कोपरा जलाशय के लिए समेकित नीति की आवश्यकता

रामसर मान्यता के बाद संरक्षण की नई जिम्मेदारियां

बिलासपुर। बनानी होगी प्रदूषण नियंत्रण नीति। समुदाय आधारित संरक्षण पर काम करना जरूरी होगा। रखना होगा कड़ा नियंत्रण अतिक्रमण और भूमि उपयोग परिवर्तन पर। निजी या खंडित स्वामित्व दृष्टिकोण से हटकर 'सार्वजनिक प्राकृतिक संपदा' घोषित करने की सख्त जरूरत है क्योंकि कोपरा जलाशय अब केवल बिलासपुर का जलाशय नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पर्यावरणीय धरोहर घोषित हो चुका है। रामसर साइट घोषित हो चुका कोपरा जलाशय अब नीति, विज्ञान और समुदाय का समन्वय मांग रहा है क्योंकि यही तीन ऐसे पक्ष हैं जिससे मजबूत संरक्षण की राह खुलेगी। सशक्त नीति का यह ढांचा कोपरा जलाशय को आने वाले दशकों में जैव विविधता और सतत विकास का मॉडल आर्द्र भूमि क्षेत्र बना सकता है। आर्द्र भूमियां प्रकृति की ऐसी संरचनाएं हैं जो जल, भूमि, जैव विविधता और मानव जीवन को एक साथ जोड़ती है। इससे जल संग्रहण को मजबूती मिलती है। कोपरा जलाशय साक्षात प्रमाण है जल संग्रहण के मामले में। बारिश के दिनों में जल संचयन कर बाढ़ की तीव्रता कम करता है। इससे ग्रीष्म काल में भूजल स्तर सामान्य बना रहता है। दोहरा लाभ यह कि भरपूर जल भंडारण की वजह से कोपरा जलाशय जलीय वनस्पतियों, मछलियों, उभयचर तथा प्रवासी पक्षियों के साथ स्थानीय पक्षियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान कर रहा है। यही वजह है कि यहां की जैव विविधता समृद्ध है। इसलिए रामसर साइट की मान्यता के बाद इसे सार्वजनिक प्राकृतिक संपदा घोषित किए जाने की जरुरत समझी जा रही है। इससे अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। कोपरा जलाशय को इसलिए अहम माना गया है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से तलछट और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से जल की गुणवत्ता में सुधार करता है। जलवायु लचीलापन

इतना ज्यादा है कि अत्यधिक बारिश, सूखा और तापमान वृद्धि जैसी परिस्थितियों में भी क्षेत्रीय जलवायु को एक स्तर पर बनाए रखने में सक्षम है। यही वजह है कि इसमें पूरे साल दुर्लभ और उपयोगी प्रजातियों को आश्रय मिलता है। जैविक संसाधनों से भरपूर कोपरा जलाशय आजीविका और सामाजिक संबंध का भी पूरा ध्यान रखता है। मछुआरों और पशुपालकों के साथ-साथ ऐसे किसानों की फसल को जीवन देता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलाशय पर आधारित हैं। इस तरह के गुणों से युक्त शायद एकमात्र जलाशय है कोपरा जलाशय। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, जल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। कैचमेंट एरिया में अनियंत्रित निर्माण और कृषि विस्तार से जलाशय का प्राकृतिक स्वरूप खत्म हो रहा है। वनों का रकबा तेजी से घट रहा है। तलछट में गाद का जमाव तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भूमि का अनियंत्रित उपयोग बढ़ा हुआ है। संरक्षण की योजनाएं हैं तो सही लेकिन शासकीय समन्वय नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए संरक्षण योजनाओं का परिणाम शून्य हो चला है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए समेकित जल प्रबंधन की प्रभावी नीति बनानी होगी। संरक्षण की योजनाओं में पंचायतों, मछुआरों और स्वयं सेवी समूहों की जिम्मेदारी तय करनी होगी। इसी तरह जलाशय में पहुंच रहे अपशिष्ट पानी का उपचार और नियंत्रित जल गुणवत्ता की जांच अनिवार्य मानी जा रही है। आधुनिक तकनीक के साथ-साथ स्थानीय अनुभव और परंपरागत जल प्रबंधन की नीतियां अपनानी होगी। रामसर साइट घोषित कोपरा जलाशय अब केवल स्थानीय जलस्रोत नहीं, बल्कि राज्य की पर्यावरणीय धरोहर है। इसके संरक्षण हेतु सशक्त प्रदूषण नियंत्रण नीति, अतिक्रमण पर कड़ा नियंत्रण और समेकित जल प्रबंधन आवश्यक है।

अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने नेवसा में चला महाअभियान नेवसा - जनपद पंचायत बिल्हा

बिलासपुर अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत लेकिन अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों को पूर्ण कराने के उद्देश्य से एनआरएलएम की विहान क्रेडर दीदियों द्वारा विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड बिल्हा के ग्राम पंचायत नेवसा में वर्ष 2016 से 2026 तक स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा हेतु विशेष निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस दौरान एफएलसीआरपी, आरबीके, सक्रिय महिला समूह की सदस्याएं, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, आवास मित्र एवं पंचायत सचिव की संयुक्त टीम ने अपूर्ण और अप्रारंभ आवासों का घर-घर पहुंचकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों से सीधे संवाद कर उन्हें 31 मार्च 2026 तक अपने आवास निर्माण कार्य को हर हाल में

पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। टीम ने निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। शासन-प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र हितग्राही आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे और सभी स्वीकृत आवास समयसीमा के भीतर पूर्ण हों। नेवसा पंचायत में चलाए गए इस महाअभियान से अपूर्ण आवासों की प्रगति में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

पुलिस ने किया ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइकः137 आरोपियों को धरपकड़ा

बिलासपुर। जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यापक रात्रि कॉबिंग गश्त अभियान चलाया। लगभग 300 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने जिलेभर में एक साथ दबिश देकर 126 वारंटियों और 11 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस अभियान से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश में मंगलवार की देर रात समस्त थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान संचालित किया गया। अलग-अलग टीमों ने संभावित ठिकानों, संदिग्ध स्थानों, होटल ढाबों और वारंटियों के निवास स्थानों पर सघन जांच की। अभियान पूरी तरह योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 126 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 50 स्थायी वारंटी और 76 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न गंभीर अपराधों में लंबे समय से फरार चल रहे 11 आरोपियों को भी पकड़कर न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने निगरानी सूची में दर्ज 41 गुंडा और बदमाशों की सघन चेकिंग की। उनकी गतिविधियों का सत्यापन कर वैधानिक चेतावनी दी गई। वहीं संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए 10 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170जिले के एसएसपी रजनेश सिंह का कहना है कि जिले को अपराध मुक्त रखना और अपराधियों पर लगाम कसने का काम पुलिस कर रही है। इसके लिए पुलिस को रात्रि गश्त और सुबह सुबह अचानक छापेमार कार्रवाई कर वारंटियों को पकड़ने का काम कर रही है। इससे अपराधियों में भी दहशत बना हुआ है। इसके साथ ही संदेहियों की धड़पकड़ करके पूछताछ की जा रही है। अपराध और अपराधियों पर लगाम कसना पुलिस की जिम्मेदारी है। और पूरी कोशिश है कि अपराधों पर नियंत्रण रख सके। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से धारदार हथियार बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि बीते एक सप्ताह में 105 लोगों पर शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है।

जंगली जानवरों के अवैध शिकार के लिए शिकारियों का बैखौफ बढ़ता जाल.....

बिलासपुर। जंगल में शिकारी सक्रिय है। शिकारी अब इतने बेखौफ हो चले हैं कि वह जंगल में खुलेआम पिंजरा लगा करके जंगली जानवरों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पाली रेंज अंतर्गत लाफा के जंगल में एक ग्रामीण ने जंगली सूअर पकड़ने के लिए तार का फंदा लगाया था। लेकिन, उसमें सूअर की जगह एक तेंदुआ फंस गया। तेंदुआ के फंसने की सूचना मिलते आसपास क्षेत्र में दहशत फैल गया। वन विभाग को जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कानन पेंडारी की रेस्क्यू टीम से मदद मांगी।घटना की जानकारी मिलने के बाद वन अमले के साथ कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत, डा. चंदन रात लगभग 10 बजे घटनास्थल व पहुंचे। फंदे में फंसा तेंदुआ छटपटा रहा था, इसलिए पहले ट्रैंक्यूलाइजर गन से

बेहोश करने का निर्णय लिया के बाद तेंदुए को फंदा से बाहर निकालने में सफलता मिली। फंदे में फंसने की वजह से तेंदुआ के पेट व पिछले हिस्से में चोट थी। समय पर रेस्क्यू करने की वजह से तेंदुआ की जान तो बच गई। लेकिन, इस घटना के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जंगल या वन्य प्राणी सुरक्षित नहीं है। शिकारी फंदा लगाकर वन्य प्राणियों की जान ले रहे हैं। इस पर कानन जू के वन्य प्राणी चिकित्सक डा. पीके चंदन दल के साथ मौके पर पहुंचे थे जहां तेंदुआ को सामान्य स्थिति में निकाल पाना मुश्किल था। इसलिए ट्रैक्यूलाइजर गन से बेहोश करने की अनुमति मांगी। पीसीसीएफ वन्य प्राणी से अनुमति मिलने के बाद सोमवार की रात एक बजे बेहोश किया और उसे फंदे से बाहर निकाला गया। उपचार के बाद तेंदुआ को जंगल में छोड़ दिया गया। एटीआर की डागी नीतू की मदद से शिकारी तक पहुंची टीम तेंदुआ, जिस फंदे में फंसा था, दरअसल वह शिकारियों की करतूत थी। आरोपित को पकड़ने के लिए कटघोरा वनमंडल ने अचानकमार टाइगर रिजर्व के डाग स्क्वाड की मदद ली। टाइगर रिजर्व की डाग नीतू जांच के दौरान नगोई भाठा निवासी विजय कुमार गोंड (37) तक पहुंच गई। तलाशी के दौरान शिकार में प्रयुक्त तार, फंदे व अन्य सामग्री बरामद हुई। आरोपित ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह सूअर का मांस खाने की लालसा में फंदा लगाया था। लेकिन, उसमें तेंदुआ फंस गया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 09, 51 व 52 के तहत प्रकरण दर्ज कर, आरोपित को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्माणाधीन पीएम आवास कॉलोनी का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

■ गुणवत्ता, विद्युत व्यवस्था एवं समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश

कोरबा। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने कोरबा स्थित दादरखुर्द क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों से आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति, प्रगति एवं शेष कार्यों की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर श्री दुदावत ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जाएं। उन्होंने पेंटिंग, इंटीरियर एवं अन्य लंबित कार्यों को समय-सीमा के भीतर सुव्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हितग्राहियों को आवास हस्तांतरण से पूर्व सभी आवश्यक कार्य पूर्ण होना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कॉलोनी के पार्ट-वन एवं पार्ट-टू के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार को निर्देशित किया कि कार्यों में तेजी लाई जाए तथा संपूर्ण निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने श्रमिकों (लेबर) की संख्या बढ़ाकर कार्य को गति देने और प्रतिदिन प्रगति की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कॉलोनी में समुचित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में निवासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने ठेकेदार एवं विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि मार्च माह तक आवास निर्माण के साथ विद्युत सहित सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिकता वाली योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आवास उपलब्ध कराना है। अत: निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय, सीईओ जिला पंचायत श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, सीडीएम कोरबा श्री सरोज महिलांगे सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सड़क, चैक एवं प्रस्तावित गौधाम-मियावाकी क्षेत्र का किया निरीक्षण, कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा पर दिया जोर' निरीक्षण के क्रम में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने तहसील रोड, बाईपास रोड (मंडी से आरएसएस नगर मार्ग) का भी निरीक्षण कर सड़क निर्माण एवं व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा यातायात सुगमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात कलेक्टर ने रिस्दी चैक, प्रस्तावित गौधाम क्षेत्र एवं विकसित किए जा रहे मियावाकी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार एवं रेल सेवा पुरस्कार-2025 (मुख्यालय) समारोह का किया गया आयोजन

■ उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले 10 अधिकारियों एवं 63 कर्मचारियों को विशिष्ट रेल सेवा एवं रेल सेवा पुरस्कार से किया गया सम्मानित

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज 13फरवरी, 2026 को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार एवं रेल सेवा पुरस्कार समारोह (मुख्यालय) के कार्यक्रम का आयोजन सायं 17.00 बजे से सेक्रसा क्रिकेट ग्राउंड, बिलासपुर में गरिमापूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ । परम्परा एवं पूरी गरिमा के साथ आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, श्री तरुण प्रकाश एवं सेक्रो अध्यक्षा, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा उपस्थित थीं । कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक सहित समस्त विभागाध्यक्ष, तीनो रेल मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक तथा बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारीगण एवं यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे । साथ ही यूट्यूब लाइव के माध्यम से रेलकर्मियों के परिवारजन व नागरिक भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम से जुड़े रहे ।आज आयोजित विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार एवं रेल सेवा पुरस्कार समारोह में सर्वप्रथम परम्परा अनुसार मुख्य अतिथि श्री तरुण प्रकाश के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ किया गया । इस अवसर पर उप महाप्रबंधक (सा.) श्री समीर कांत माथुर के द्वारा सभी अतिथियों व आगंतुकों का स्वागत किया गया तथा रेलवे के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला । साथ ही भारतीय रेलवे की गौरवशाली यात्रा पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया तथा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई । इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने अपने संबोधन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार एवं रेल सेवा पुरस्कार समारोह की बधाई दी तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की निरंतर प्रगति एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार व्यक्त किया । श्री तरुण प्रकाश ने कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की समर्पित रेल कर्मियों की निष्ठा और लगन से इस वर्ष दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को रेल मंत्रालय स्तर पर तीन महत्वपूर्ण शील्ड प्रदान किए गए हैं, उन्होने इसकी भूरिङ्भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे परिवार अपनी एकाग्रता एवं लगन से कार्य करते हुए रेलवे की उन्नति की परंपरा को बनाए रखेगी ।रेल पुरस्कार समारोह में समर्पित रेलकर्मियों को सम्मानित करने का यह एक गरिमामय मंच है, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से संगठन का गौरव बढ़ाया है। आज इस अवसर पर19 मेजर शील्ड, 37 माइनर शील्ड, 60 विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार एवं 13 रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, जो संगठन की सामूहिक उत्कृष्टता तथा कर्मियों की असाधारण सेवाओं का प्रतीक हैं । मैं आज सम्मानित होने वाले सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रत्येक मापदंडों पर बेहतर कार्य निष्पादन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर तीनों मंडलों में से बिलासपुर रेल मंडल को सर्वोत्तम प्रदर्शन हेतु प्रतिष्ठित ओवरऑल एफिशिएंसी'' सतपुड़ा शील्ड से नवाजा गया। यह समारोह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कर्मचारियों के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट सेवा भावना का प्रतीक रहा।

महाशिवरात्रि पर भांग क्यों पी जाती है?

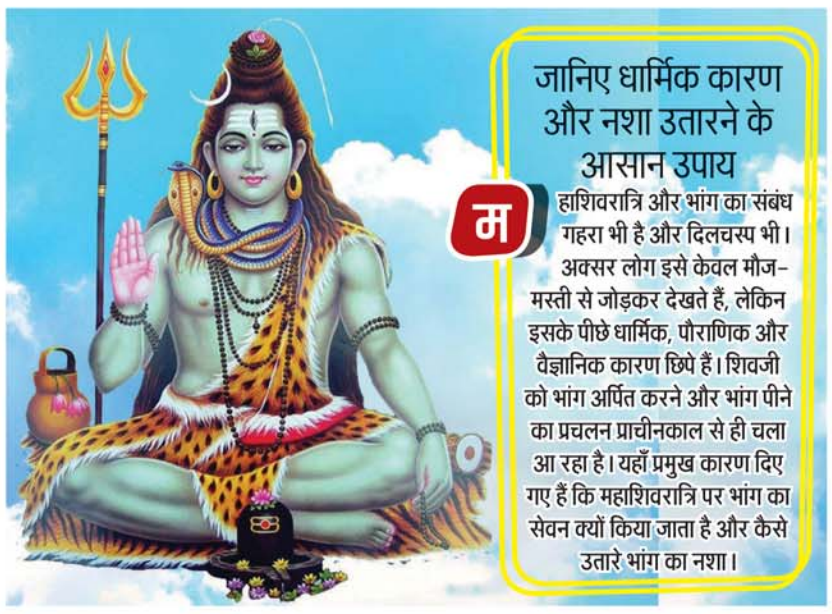

जानिए धार्मिक कारण और नशा उतारने के आसान उपाय

महाशिवरात्रि और भांग का संबंध गहरा भी है और दिलचस्प भी। अक्सर लोग इसे केवल मौज-मस्ती से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। शिवजी को भांग अर्पित करने और भांग पीने का प्रचलन प्राचीनकाल से ही चला आ रहा है। यहाँ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि महाशिवरात्रि पर भांग का सेवन क्यों किया जाता है और कैसे उतारे भांग का नशा।

1. हलाहल विष का प्रभाव कम करना

पौराणिक कथा के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब 'हलाहल' नामक भयंकर विष निकला, तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता से शिव का शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा। मान्यताओं के अनुसार, भांग, धतूरा और बेलपत्र जैसी औषधियों में शीतलता होती है, जिनका उपयोग शिव के शरीर की गर्मी और विष के प्रभाव को शांत करने के लिए किया गया था। देवताओं ने इसका लेप बनाकर उनके शरीर पर लगाया था।

2. शिव के 'आनंद' स्वरूप का प्रतीक

भगवान शिव को 'औघड़' और 'विरागी' माना गया है। वे संसार के मोह-माया से दूर गहरे ध्यान में रहते हैं। भांग को एक ऐसी औषधि माना जाता है जो एकाग्रता बढ़ाने और मन को बाहरी दुनिया से काटकर अंतर्मन से जोड़ने में मदद करती है। भक्त इसे शिव के इसी दिव्य आनंद के प्रसाद के रूप में लेते हैं, लेकिन यहां यह स्पष्ट करना है कि शिवजी भांग नहीं पीते थे। प्राचीन काल में भांग को एक महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी माना जाता था। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में आती है, जब मौसम बदल रहा होता है। आयुर्वेद के अनुसार, सीमित मात्रा में भांग का सेवन पाचन में सुधार और शरीर की थकान दूर करने में सहायक होता था। इसे 'विजया' भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुखों और रोगों पर विजय पाने वाली।

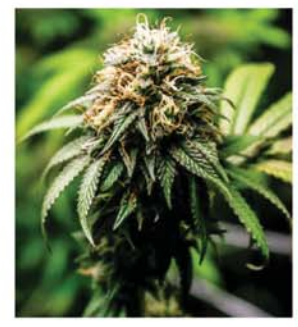

महाशिवरात्रि के बाद लगने वाला है सूर्य ग्रहण

इस साल का पहला सूर्य ग्रहण महाशिवरात्रि के बाद लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर शुरू होगा और समाप्त शाम 7 बजकर 57 मिनट पर होगा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में चंद्र और सूर्य दोनों ग्रहण को अशुभ माना गया है। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर इन 5 राशियों पर पड़ने वाला है। इन राशि के जातकों के लिए पूरा एक महीना कष्टकारी रहेगा। इन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि साल का पहला सूर्य किन राशियों के लिए अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है।

किसकी याद में मनाया जाता है वैलेंटाइन डे

वैलेंटाइन वीक के हर दिन को खास तरीके से मनाया जाता है और अंत में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। आपको मालूम हो कि वैलेंटाइन डे रोम के एक पादरी वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है। संत वैलेंटाइन ने अपने प्राण तक दे दिए थे। संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने वाले दिन को ही वैलेंटाइन डे के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन प्यार करने वाले जोड़े एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं और गिफ्ट देते हैं. क्या वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे की पूरी कहानी।

संत वैलेंटाइन को क्यों दी गई थी मौत की सजा

तीसरी शताब्दी में रोम पर सम्राट क्लॉडियस द्वितीय का राज था। क्लॉडियस का मानना था कि अविवाहित सैनिक शादीशुदा सैनिकों की तुलना में अच्छे योद्धा साबित हो सकते हैं क्योंकि उनको परिवार की चिंता नहीं होती। अपनी इसी सोच के चलते सम्राट क्लॉडियस द्वितीय ने रोम में विवाह बंद करवा दिए। सम्राट के इस आदेश से रोम के लोग काफी दुखी हो गए। प्रेम करने वालों पर तो मानों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पादरी वैलेंटाइन को भी सम्राट क्लॉडियस का यह आदेश पसंद नहीं था। वैलेंटाइन ने रोम के सैनिकों व लोगों को राजा के इस आदेश को नहीं मानने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। संत वैलेंटाइन इतने से ही चुप नहीं रहे बल्कि वह छिपकर प्रेमी जोड़ों का विवाह ईसाई परंपरा से कराते रहे। संत वैलेंटाइन का मानना था कि प्रेम कोई अपराध नहीं, बल्कि भगवान की देन है। कुछ समय बाद राजा क्लॉडियस को जब इस बारे में पता चला तो वह संत वैलेंटाइन पर बहुत ही क्रोधित हुआ। राजा ने वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने का फरमान सुना दिया। संत वैलेंटाइन को राजा के आदेश के उल्लंघन और विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया। रोम के लोगों का कहना था की वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी, जिससे वो लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकते

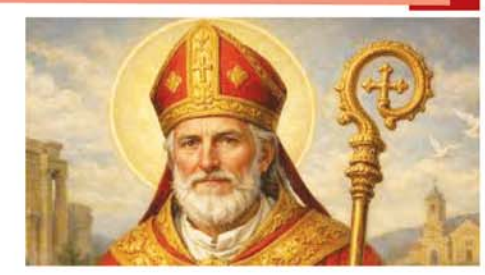

थे। जेलर की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकात के बारे में पता था इसलिए उसने वैलेंटाइन से मदद मांगी। वैलेंटाइन ने जेलर की अंधी बेटी की आंखों को अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और जेलर के बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। फांसी पर चढ़ने से पहले वैलेंटाइन ने अपनी प्रेमिका के लिए एक खत लिखा, खत के अंत में लिखा था, 'योर वेलेंटाइन'। यही विश्व का पहला वैलेंटाइन संदेश माना जाता है। कहा जाता है 270 ईस्वी में 14 फरवरी के दिन संत वैलेंटाइन को फांसी दी गई थी। रोमवासियों को संत वैलेंटाइन को फांसी पर लटकाना सही नहीं लगा। उन्होंने संत वैलेंटाइन की फांसी के दिन यानी 14 फरवरी को हर साल प्यार के दिन के रूप में मनाना शुरू कर दिया। पोप गेलैसियस ने 496 ईस्वी में इस तारीख को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा।

साड़ी-लहंगे के साथ ऐसे चुनें चूड़ियों के सही कलर

साड़ी, कुर्ता या फिर लहंगा जैसे ट्रेडिशन इंडियन वियर के साथ हाथों में चूड़ी बेहद खूबसूरत लगती है। बगैर चूड़ी के भी जैसे महिला की सुंदरता और श्रृंगार अधूरा सा लगता है, लेकिन अगर आप अभी भी वहीं कपड़े से मैच करती चूड़ियों को पहनकर तैयार हो जाती हैं। तो आज से ही बंद कर दें। जान लें कौन से रंग की साड़ी या कुर्ते के साथ कौन से रंग की चूड़ी जचेंगी। इमेज कोच साक्षी ने वीडियो शेयर कर डिटेल में समझाया है कि कौन से कलर के आउटफिट या इंडियन वियर के साथ कौन से रंग की चूड़ियों को पहनें जिससे ट्रेंडी लुक मिले। जान लें कौन से रंग की चूड़ियों को करें मैच

नीले रंग के कुर्ते या साड़ी के साथ

अगर आपका आउटफिट नीले रंग का है। जैसे नीला कुर्ता, साड़ी या फिर लहंगा तो ऐसे कपड़े के साथ ऑरेंज या फिर गोल्डन कलर की चूड़ियों को मैच करके पहनें। ये आपके नीले रंग के कुर्ते में चार चांद लगा देगी।

पीला रंग का कुर्ता

अगर आउटफिट पीले रंग का है तो इसके साथ पर्पल या मरून शेड की चूड़ियों को मैच करें। इससे पीले रंग का कपड़ा खिलकर रंग बिखेरेगा।

ब्लैक या व्हाइट कुर्ता या साड़ी के साथ

अगर आप ब्लैक या व्हाइट कलर के एथिनिक वियर जैसे कुर्ता या साड़ी को पहन रही हैं तो परफेक्ट वाइब्स के लिए मल्टी कलर की चूड़ियों को पहनें।

रेड कलर के आउटफिट के साथ कौन से रंग की चूड़ी पहनें

अगर आपकी साड़ी, सूट या लहंगा लाल रंग का है तो मैचिंग चूड़ियां पहनने की बजाय एमरॉल्ड ग्रीन या फिर ऑफ व्हाइट कलर की चूड़ियों को मैच करें।

ग्रीन आउटफिट के साथ चूड़ियों का कलर

अगर आउटफिट ग्रीन कलर का है तो ऐसी चूड़ियों के साथ हॉट पिंक, या वर्क के अर्कोडिंग गोल्डन या सिल्वर कलर की पहनें। इससे आपको रीगल लुक मिलेगा।

किचन के काम आने वाले कुछ खास कुकिंग टिप्स

किचन के कई काम ऐसे हैं, जिन्हें करने में समय लगता है। तो वही कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें बनाने में समय लगता है। खासतौर पर अगर आप किचन के लिए बिगिनर्स हो तो ये समय काफी ज्यादा होता है। चटोरी चेतना एक बार फिर से आपके लिए किचन के कमाल के हैक्स लेकर आई हैं, जो आपके किचन के मुश्किल कामों को आसान कर देंगे। उन्होंने 5 कुकिंग हैक्स शेयर किए हैं, जिससे खाना भी टेस्टी बनेगा और आपको घंटों मेहनत नहीं करनी होगी। चलिए बताते हैं क्या हैं खास कुकिंग हैक्स-

भरवां पराठा

आलू, प्याज, गोभी, पनीर का पराठा बनाना लगता है मुश्किल तो बस ये हैक कर लें ट्राई। पतला आटे की 2 लोई अलग-अलग पहले बेल कर रख लें। अब एक रोटी पर पर स्टफिंग वाला सामान रखें इसके बाद दूसरी बेली हुई रोटी को ऊपर से लगा दें। फिर इसे हल्के हाथों से बेलकर पराठा सेंक लें। भरवा पराठा आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा।

खस्ता कचौड़ी-पूड़ी

समय कम है और पूड़ी-कचौड़ी, डोसा को खस्ता बनाना है, तो आटे में सूजी जरूर मिलाना। सूजी आपकी सभी चीजों को खस्ता कर देगी और स्वाद भी गजब का देगी। डोसा, कचौड़ी, पूड़ी के आटे में इसे मिलाकर बनाएं और क्रिस्पी पूड़ियां लोगों को खिलाएं।

आलू कैसे उबालें

आलू हमेशा छीलने के बाद उबालें, इससे इन्हें गर्म-गर्म छीलने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप बस इन्हें उबालकर मैशर से फोड़कर मैश कर लें। काम आसान हो जाएगा।

बेसन में पड़ गई गुठली

बेसन को घोल बनाते समय उसमें पड़ जाती है, गुठलियां तो मिक्स करें पानी और दूध। पानी के साथ जरा सा दूध मिलाएं और इन गुठलियों से परमानेंट छुटकारा पाएं

सब्जी का स्वाद कैसे बढ़ाए

सब्जी का स्वाद है बढ़ाना तो मसाले को भूनकर डालना। जीरा, साबुत धनिया जैसे मसालों को तवे पर रोस्ट करें और फिर मसाले में इस्तेमाल करें। सब्जी का स्वाद और खुशबू बिल्कुल अलग आएगी।

कंबल को स्टोर करने का सुरक्षित और डस्ट फ्री तरीका

ठंड के दिनों कंबल इधर-उधर फैले रहते हैं। वहीं सर्दी खत्म होने के बाद इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए सोचना पड़ता है। ब्लैंकेट स्टोरेज बैग्स इसका एक सुरक्षित और आसान तरीका हैं। इनमें ब्लैंकेट डस्ट फ्री और पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं, साथ ही इनके स्टोरेज में भी आसानी होती है। ये स्पेशियस होते हैं और कंबल के साथ ही ठंड के कपड़े आदि को स्टोर करने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होंगे। इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। यानी इन्हें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

फोल्डेबल स्टील फ्रेम क्लॉथ/ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजर बैग की कैपेसिटी बहुत है। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली काफी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी खास कर सर्दियों में कंबल रखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये 2 के सेट में आएंगे, जिनमें आपके डबल बेड के 2 कंबल आराम से आ जाएंगे। इसमें जिप लॉक भी मिलेगा ताकि आपका कंबल पूरी तरह सुरक्षित रहे।

एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज बॉक्स बड़े काम की चीज है। ये काफी स्पेशियस है, जिसमें नियमित इस्तेमाल की कई सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। सर्दियां खत्म होते ही कंबल के रख रखाव को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस बैग की मदद ले सकती हैं। इसका मटेरियल इ्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें जिप लॉक और हैंडल भी आएगा। आप चाहें तो इसमें ठंड के कपड़े भी स्टोर कर सकती हैं।

मॉइश्चर प्रूफ

रेक्टेंगुलर स्टोरेज बैग ब्लैंकेट स्टोरेज के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये स्टोरेज बैग बड़े काम की चीज हैं। कंबल के अलावा भी इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कपड़े या फिर ठंड के कपड़े स्टोर कर सकती हैं। ये जिप लॉक के साथ आयेंगे, जिससे आपके सामान पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। स्टोरेज ऑर्गेनाइजर आप सभी के पास होना चाहिए। कंबल को सुरक्षित रूप से रखना हो या ठंड के कपड़े रखने हों, ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आपके बड़े काम आएगा। इनमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड और सुरक्षित रहती हैं। साथ ही इसमें जिप लॉक मिल जाएगा, इस तरह इनमें रखे सामान धूल गंदगी से भी बचे रहते हैं।

बाजरे की रोटी फट जाती है, फूलती नहीं? फॉलो करें टिप्स

सर्दियों में स्पेशल बनने डिशेज में से एक है बाजरे की रोटी। गरमा-गरम बाजरे की रोटी पर घी लगाकर खाने का मजा ही कुछ और है। ये टेस्टी भी होती हैं और हेल्दी भी। साथ ही इनकी तासीर भी गर्म होती है, इसलिए विंटर्स के लिए परफेक्ट रहती हैं। हालांकि बाजरे की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गृहणियों की अक्सर शिकायत रहती है कि कितनी भी कोशिश कर लो बाजरे की रोटी में क्रैक आ ही जाते हैं। ये बेलते या सेंकते टाइम फट जाती है या टूट जाती है। वहीं आमतौर पर फूलती भी नहीं और सख्त भी बनती है। दरअसल बाजरे में ग्लूटेन की कमी के कारण ही इसकी रोटियां बनाना मुश्किल होता है। हालांकि अगर आप ये छोटी-छोटी टिप्स फॉलो करें तो बाजरे की रोटियां बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये एकदम सॉफ्ट और फूली-फूली बनेंगी।

बाजरे की रोटी तभी अच्छी बनेंगी, जब इसका आटा अच्छी तरह लगा हुआ होगा। इसलिए आटा गूंथने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से आटा गूंथने पर फटता है और रोटियां अच्छी नहीं बनतीं। बस थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी डालकर आटा गूंथ लें, इससे आटा सॉफ्ट हो जाता है। इस दौरान आटे को थोड़ा मसले भी ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए। बाजरे के आटे को गूंथने के बाद तुरंत उसकी रोटियां ना बनाएं। ऐसा करने से आटा अच्छी तरह सेट नहीं हो पाता और रोटियां सही नहीं बनती हैं। गूंथने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए आटे को ढककर छोड़ दें। ऐसा करने से आटा सेट हो जाता है और रोटी बेलने में आसानी होती है। आटे से एक लोई बनाएं, फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें ताकि ये चिपके ना। बेलन से इसे बेलना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए हाथ से थपथपाकर ही गोल रोटी की शेप दें। रोटी बेलने के बाद हमेशा गर्म तवे पर ही डालें। ठंडे तवे पर डालने से रोटी काफी सख्त बनती है और टूट भी जाती है। इसलिए पहले तवे पर गर्म कर लें, उसके बाद ही रोटी सेंकने के लिए डालें। बाजरे की रोटी को सेंकते हुए बहुत ज्यादा पलटना नहीं चाहिए। इससे रोटी टूट जाती है। आपको इसे सेंकते हुए सिर्फ तीन बार ही पलटना है। इतना काफी होता है। बाजरे की रोटियां एकदम फूली-फूली और नर्म बनें, इसके लिए ये पानी वाली ट्रिक जरूर ट्राई कर के देखें। इसके लिए जब आप तवे पर रोटी सेंकने डालें तो उसकी दूसरी तरफ थोड़ा सा पानी लगा दें। पानी सूखने के बाद 15 सेकंड के अंदर रोटी को पलटा दें। दूसरी तरफ से भी रोटी बढ़िया से सेंके। एकदम फूली फूली बाजरे की रोटियां बनेंगी।

ब्रेड रोल फ्राई करने से पहले जान लें ये सीक्रेट टिप्स

शाम की भूख हो या मेहमानों के लिए कुछ झटपट बनाना हो, ब्रेड रोल हर किसी की पसंद होते हैं। बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट ब्रेड रोल अगर ज्यादा तेल सोख लें, तो स्वाद भारी और खाने के बाद असहज महसूस हो सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ सही तरीकों को अपनाकर ब्रेड रोल को कम तेल में भी परफेक्ट बनाया जा सकता है।

ब्रेड को सही तरीके से तैयार करें: ब्रेड रोल बनाने में सबसे पहली गलती ब्रेड को ज्यादा भिगो देना होती है। ब्रेड स्लाइस को पानी में डुबाने की बजाय हल्का सा पानी लगाएं और तुरंत निचोड़ लें। ज्यादा नमी होने पर ब्रेड तलते समय तेल सोखने लगती है। (पानी की जगह ठंडे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।)

स्टफिंग होनी चाहिए सूखी: ब्रेड रोल की स्टफिंग जितनी सूखी होगी, रोल उतने ही कम तेल सोखेंगे। आलू या सब्जियों को अच्छे से भूनें ताकि उनमें मौजूद नमी निकल जाए। स्टफिंग को पूरी तरह ठंडा होने दें, क्योंकि गरम भरावन से भाप बनती है और तेल ज्यादा लगता है।

बाइंडिंग के लिए सही चीजें मिलाएं: स्टफिंग में 1–2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ब्रेडक्रंब्स या भुना हुआ सूजी मिलाने से अतिरिक्त नमी एब्जॉर्ब हो जाती है। इससे रोल फ्राई करते समय खुलते नहीं और तेल भी कम सोखते हैं।

तेल का तापमान है सबसे अहम: तेल अगर ठंडा होगा तो ब्रेड रोल स्पंज की तरह तेल पी जाएंगे। वहीं बहुत ज्यादा गरम तेल में रोल बाहर से जल सकते हैं। इसलिए हमेशा मध्यम आंच पर तेल गरम करें और टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्रेड डालकर देखें- अगर वह धीरे-धीरे ऊपर आ जाए, तो तेल सही है।

तलते समय इन बातों का रखें ध्यान: ब्रेड रोल को तेल में डालते ही बार-बार ना पलटें। पहले एक साइड अच्छे से सेट होने दें, फिर पलटें। बहुत ज्यादा धीमी आंच पर तलने से बचें, क्योंकि इससे रोल ज्यादा तेल सोखते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें।

फ्रिज ट्रिक अपनाएं: अगर समय हो, तो तैयार रोल्स को तलने से पहले 10–15 मिनट फ्रिज में रख दें। ठंडे रोल्स तेल में डालते ही जल्दी सेट हो जाते हैं और तेल कम लगता है। तलने के बाद क्या करें: ब्रेड रोल्स को तेल से निकालते ही किचन टिश्यू या पेपर नैपकिन पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए। इससे रोल हल्के और कुरकुरे बने रहते हैं। हेल्दी विकल्प भी आजमाएं: अगर आप और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो ब्रेड रोल को एयर फ्रायर या ओवन में भी बना सकते हैं। इसमें बहुत कम तेल लगता है और स्वाद भी बरकरार रहता है।

डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का भव्य स्वागत, डी.ए.वी. संस्थान के कार्यों की सराहना

बेमेतरा। डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता में बीते दिवस शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण अवसर देखने को मिला, जब प्रदेश के कैबिनेट शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का डी ए वी जांता विद्यालय परिसर में आगमन हुआ। उनके आगमन पर विद्यालय परिवार द्वारा पारंपरिक एवं आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत-अभिनंदन से हुई, जहाँ विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा पुष्पगुच्छ, श्री फल, साल भेंट कर शिक्षा मंत्री का सम्मान किया गया। इसके पश्चात शासकीय हाई स्कूल जांता प्रांगण में भी उनका स्वागत किया गया, जहाँ पूरे क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों ने एकजुट होकर इस भव्य आयोजन को सफल बनाया।इस अवसर पर डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल,शास हाई स्कूल,मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल, छात्रावास जांता, के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन किया गया। सभी शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा के प्रति अपनी एकजुटता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता के शैक्षणिक वातावरण, भौतिक सुविधाओं एवं शिक्षण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, शिक्षकों की मेहनत एवं अनुशासित वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सी बी एस ई अंग्रेजी माध्यम के साथ व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है।इसी क्रम में शिक्षा मंत्री ने डी.ए.वी. संस्थान छत्तीसगढ़ के प्रमुख रीजनल ऑफिसर प्रशांत कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में संचालित प्रदेश की सभी 72 मुख्यमंत्री स्कूलों के सुचारू रूप से संचालन की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि डी.ए.वी. संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री स्कूलों को जिस गुणवत्ता, अनुशासन एवं समर्पण के साथ संचालित किया जा रहा है, वह राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण डी ए वी जांता के उत्कृष्टता व छात्र-छात्राओं के अनेक उपलब्धियां हैंकार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत, देशभक्ति व होली नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई, जिनकी शिक्षा मंत्री ने खुले मंच से सराहना की। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देखकर उन्होंने उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के मॉडल को अपनाते हुए प्रदेश के 150 विद्यालयों को सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर विकसित किया जाएगा। यह निर्णय विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा।इसी दौरान डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता में प्रवेश उत्सव के अंतर्गत बनाए गए आकर्षक सेल्फी जोन में शिक्षा मंत्री ने फोटो खिंचवाया और इस नवाचार की सराहना की। विद्यालय ने जानकारी दी कि डी.ए.वी.संस्थान में नर्सरी से कक्षा 11 वीं तक प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का प्रवेश शीघ्र कराकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण, अनुशासित एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करें।शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया, वहीं शिक्षकों से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य पी एल जायसवाल एवं डी.ए.वी. संस्थान की ओर से शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को स्मृति-चिह्न भेंट कर आभार व्यक्त किया गया।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 20 लाख की लागत से निर्माण होने वाले सामुदायिक भवन का हुआ भूमिपूजन

कवर्धा। कवर्धा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 10 में लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास विधायक निधि मद अंतर्गत 20 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन निर्माण का भूमिपूजन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष सहित उपस्थित अतिथियों ने किया। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने बताया कि वार्डवासियों द्वारा लंबे समय से सामुदायिक भवन निर्माण की मांग की जा रही थी जिसके लिए उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने अपने विधायक निधि से 20 लाख रूपए राशि प्रदान की गई थी जिसका विधिवत निविदा प्रक्रिया किया जाकर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास निर्माण होने वाले सामुदायिक भवन का आज विधिवत पूजा अर्चना कर नींव रखा गया। उन्होनें बताया कि वार्डवासियों का मांग ।

होली से पहले गन्ना किसानों को राहत, भोरमदेव शक्कर कारखाने ने जारी किए 4.73 करोड़ रुपए

कवर्धा। होली से पहले भोरमदेव शक्कर कारखाने से जुड़े गन्ना किसानों के लिए राहतभरी खबर है। कारखाने ने किसानों के खातों में 4 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि जारी की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्साह का माहौल बन गया है। चालू पेराई सत्र में अब तक 14,518 किसानों को कुल 51 करोड़ 51 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। समयबद्ध भुगतान से किसानों में भरोसा मजबूत हुआ है और खेती-किसानी के साथ त्योहारी तैयारियों को भी बल मिला है।

प्रशासनिक मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया निरंतर जारी रहने की जानकारी कारखाना प्रबंधन ने दी है। उत्पादन के मोर्चे पर भी कारखाना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब तक 2 लाख 42 हजार 990 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे 2 लाख 86 हजार 743 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। प्रबंधन का मानना है कि किसानों के सहयोग और सुव्यवस्थित संचालन से इस वर्ष बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। कारखाना प्रशासन ने सदस्य और गैर-सदस्य किसानों से सर्वे के अनुरूप अधिक से अधिक गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है, ताकि पेराई लक्ष्य समय पर पूरा हो सके और सहकारी व्यवस्था मजबूत बनी रहे। किसानों को एफआरपी के अतिरिक्त रिकवरी राशि, बोनस, रियायती दर पर शक्कर वितरण, उन्नत बीज और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। साथ ही श्रमिकों और किसानों के लिए सस्ती भोजन व्यवस्था जैसी पहलें सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाती हैं।

छत्तीसगढ़ के पहली यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड प्राप्त छात्रा साक्षी जायसवाल को शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के पहली युवा यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड प्राप्त छात्रा साक्षी जायसवाल जिसके पिता जिले के ही डी ए वी स्कूल जांता के प्राचार्य पद पर पदस्थ हैं। सुपुत्री साक्षी जायसवाल छत्तीसगढ़ के पहली बालिका बॉल वैज्ञानिक हैं जिन्होने अब तक अनेक अवॉर्ड प्राप्त कर चूंकि हैं, अब तक उन्हें भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय पी एम ओ , तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री,बिहार के मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री, व दिल्ली के मंत्री व चेन्नई के राज्य पाल ने चेन्नई के राजभवन में सर्टिफिकेट ,मोमेंटो से सम्मानित हो चुकी हैं।

नेशनल स्पेश डे, के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ से मात्र एक बालिका वैज्ञानिक छात्रा साक्षी जायसवाल यंग साइंटिस्ट इंडिया के ग्रैंड फिनाले में भाग लेकर, 23 अगस्त 2023 एवं 23 अगस्त 2024 एवं 23 अगस्त 2025 के लगातार तीन वर्ष तक चयनित होकर, बतौर बाल वैज्ञानिक बनकर पहुँची थी जिन्हें चेन्नई के राज भवन में प्रधानमंत्री जी के सलाहकार एवं चेन्नई के राज्यपाल टी एन रवि जी ने पहले बालिका युवा वैज्ञानिक से सम्मानित किए हैं। एवं लेफ्टिनेंट जनरल बी एस खण्डारे दिल्ली, रूसी व कजाकिस्तानी के अंतरिक्ष यात्री, नासा व इसरो सहित देश व विदेश से आये अनेक वैज्ञानिकों ने साक्षी जायसवाल को यंग साइंटिस्ट इंडिया अवॉर्ड से सम्मानित कर चुके हैं।. शीर्षकः प्रकाश का उपयोग करके डेटा स्थानांतरण हेतु वायरलेस संचार तकनीक का आविष्कार करने वाले भारत कर पहले कम उम्र के बालिका बाल वैज्ञानिक का वर्ड रिकॉर्ड गोलडन बुक ऑफवर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हूँ मैं 12 वर्ष 19 दिन मात्र। . अखिल भारतीय कलाल, कलवार, कलार महासभा नई दिल्ली द्वारा कलचुरी गौरव रत्न 2025 से अलंकृत किया गया हैं। माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने साक्षी जायसवाल को अपने कर कमलों से गोल्ड मैडल व युवा वैज्ञानिक गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से साक्षी को सम्मानित किए हैं , शिक्षा मंत्री जी ने साक्षी छत्तीसगढ़ के पहली बालिका बाल वैज्ञानिक बनने पर उन्हें बधाई देते हुए शुभकामनाएं दिए हैं, साक्षी ने गोल्डन बुल ऑफवर्ल्ड रिकॉर्ड महज 12 वर्ष 19 दिन में यह रिकॉर्ड बनाई है, मंत्री ने साक्षी के सराहना किए साक्षी जायसवाल ऐसे बालिका बाल वैज्ञानिक है उनसे प्ररेणा लेकर हमारे अन्य बच्चे भी वैज्ञानिक प्रतिभा को निखार पाएंगे साक्षी जायसवाल वैज्ञानिक बेटी ने निश्चित ही बेमेतरा जिले के साथ -साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य व देश का नाम भी नाम रौशन कर रही हैं।

चमचमाती सड़क से राह होगा आसान, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया सड़क मार्ग का भूमिपूजन

कवर्धा। कवर्धा शहर के प्रमुख मार्ग व नगरवासियों की बहुप्रतिक्षित मांग अंबेडकर चौक से लेकर समनापुर मार्ग तक 2 करो? 60 लाख रूपए की लागत से निर्माण होने वाले बीटी रोड, आरसीसी नाली निर्माण एवं 20 लाख रूपए निर्माण होने वाले सामुदायिक भवन निर्माण का विधिवत भूमिपूजन आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी एवं उपस्थित अतिथियों ने किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नगर के विकास के लिए सड़क, नाली और सामुदायिक भवन जैसे मूलभूत कार्य अत्यंत आवश्यक हैं। अंबेडकर चौक से समनापुर पुल तक लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड एवं नाली का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने मोहल्लावासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा शहर में चल रहे निर्माण कार्यो की जानकारी उपस्थित लोगों को देते हुए कहा कि कवर्धा शहर चहुमुंखी विकास की ओर अग्रसर है अंबेडकर चौक के पास 30 लाख रुपए की लागत से सियान सदन बनाया जाएगा, जहां वरिष्ठ नागरिक बैठकर समय व्यतीत कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें घर से लाने-ले जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। शहर के सभी प्रमुख चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए भी 20-20 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने वाली है, जिसमें गाडगे जी, सहस्त्रबाहु जी, सेन जी और महाराज करपात्री जी महाराज से जुड़े चौकों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही कवर्धा कॉलेज परिसर में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नालंदा परिसर के रूप में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। भोजपुरी तालाब के समीप हनुमंत वाटिका का निर्माण किया जा चुका है, वहीं घोटिया क्षेत्र में 354 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रायपुर बिलासपुर मार्ग के 7.8 किलो मीटर हिस्से को फोरलेन बनाते हुए कवर्धा एंट्रेंस का विकास किया जाएगा, जिसके लिए 54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं । नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि कवर्धा शहर सहित पूरे जिले में चहुमुंखी विकास हो रहा है विकास की गंगा बह रही है। विकास पुरूष व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में हो रहे कार्य इतिहास के पन्नों में लिखा जावेगा। यह पूरे शहर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ से अधिक लागत से गौरव पथ रोड का निर्माण कराया जा रहा है। ठाकुर देव से नया बस स्टैंड तक तक 11 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शहीद वीर स्तंभ चौक में शहीदों की प्रतिमा स्थापित की गई है और शहर के हर क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। चौपाटी, हनुमंत वाटिका और बूढ़ा महादेव मंदिर में कांवडियों के विश्राम के लिए निर्माण किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि समनापुर मार्ग अत्यंत जर्जर हो चुका है जिसके कारण उस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था आज 2 करोड़ 60 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले बीटी रोड व नाली निर्माण का भूमिपूजन किया गया, सड़क निर्माण होने से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष नितेश अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, डॉ. बीरेन्द्र साहू, मनिराम साहू, विजय पाटिल, नगर पालिका उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, पार्षद बिहारी धुर्वे, अजय ठाकुर, योगेश चंद्रवंशी, दीपक सिन्हा, केशरीचंद सोनी, संजीव कुर्रे, श्रीमती सुषमा उपाध्याय, भुनेश्वर चंद्राकर, उमंग पाण्डेय, डॉ. आनंद मिश्रा सहित जनप्रतिनिधिगण अधिक संख्या में उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 20 लाख की लागत से निर्माण होने वाले सामुदायिक भवन का हुआ भूमिपूजन

कवर्धा। कवर्धा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 10 में लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास विधायक निधि मद अंतर्गत 20 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन निर्माण का भूमिपूजन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष सहित उपस्थित अतिथियों ने किया। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने बताया कि वार्डवासियों द्वारा लंबे समय से सामुदायिक भवन निर्माण की मांग की जा रही थी जिसके लिए उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने अपने विधायक निधि से 20 लाख रूपए राशि प्रदान की गई थी जिसका विधिवत निविदा प्रक्रिया किया जाकर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास निर्माण होने वाले सामुदायिक भवन का आज विधिवत पूजा अर्चना कर नींव रखा गया। उन्होनें बताया कि वार्डवासियों का मांग पूरा हो जाने से अब सुख-दुख जैसे कार्यक्रमों के लिए परेशान नही होना पड़ेगा एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहूलियत मिलेगी। एक छत के नीचे अपना कार्य निपटा सकेगें। वार्डवासियों ने सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति देने व भूमिपूजन के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आभार जताया।

उपमुख्यमंत्री ने पात्र हितग्राहियों को मिला सिलेण्डर व चूल्हा बांटे-कवर्धा प्रवास में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीटी रोड एवं नाली निर्माण भूमिपूजन के उपरांत कवर्धा शहर के पात्र हितग्राहियों को मंच से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेण्डरएवं चूल्हा का वितरण किया। उन्होनें सभी हितग्राहियों को बधाई व शुभकामनाएं दी।

वार्षिकोत्सवः शिक्षित और जागरूक व्यक्ति ही देश की असली पहचान

बेमेतरा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंदगांव में वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच आनंदगांव चंद्रकिरण नायक, मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, विशिष्ट अतिथियों में प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड प्रहलाद रजक, अध्यक्ष भाजपा भिंभौरी मंडल सूर्यकांत नायक, जनपद सदस्य सरोज यादव, उपसरपंच तिलोषमा धीवर सहित शाला के समस्त शिक्षक एवं स्टॉफ शामिल रहे। पूर्व विधायक चंदेल ने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान, अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायक होता है। उन्होंने शिक्षा के साथ खेलकूद में सहभागिता का संदेश दिया। सरपंच चंद्रकिरण ने विद्यार्थियों को अनुशासन और नियमित सहभागिता के महत्व को समझाया। शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष सूर्यकांत ने खूब पढ़बो, खूब बढ़बो का नारा देते हुए बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले ओम यदु को ट्रेकशूट एवं थर्मस देकर सम्मानित किया गया। जंबूरी स्काउट-गाइड में शामिल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ईको क्लब के श्रेष्ठ सदस्यों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य तारकेश्वर साहू ने डिलेश कोसले को बेस्ट छात्र का पुरस्कार स्मृति चिन्ह एवं ?1100 के साथ प्रदान किया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का संचालन सी.के. साहू एवं मनोज वर्मा ने किया।

80 फीसदी से अधिक अंक पाने वाले छात्र सम्मानित हुए-कार्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मनोज कुमार वर्मा, व्याख्याता ने अपने पिता स्व. पुनऊराम वर्मा की स्मृति में कक्षा 12वीं के किरण वर्मा (88.4त्न), संगीता यादव (88.2त्न) तथा कक्षा 10वीं की दिव्या ध्रुव (90त्न), दुष्यंत यादव (84त्न) एवं लीला (82त्न) को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। इसी कड़ी में श्रीमती नेहा गुप्ता व्याख्याता के द्वारा दसवीं कक्षा में गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका लीला को नकद 500 रुपए प्रदान किया गया। विद्यालय की वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती बी. मांडले मैडम के द्वारा वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागी विद्यार्थियों को पचास-पचास रुपए आशीर्वाद एवं प्रेरणा स्वरूप प्रदान किया गया।

विदाई समारोह का आयोजन-कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों के अंतिम दिन को यादगार बनाने के लिए सफल प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका श्री भागवत प्रसाद बानी का रहा। सभी विद्यार्थी बहुत ही उत्साहित रहें। विदाई समारोह के अंतिम में प्रत्येक वर्ष की भांति बानी परिवार की ओर से स्टूडेंट ऑफ़द ईयर 2026 की घोषणा की गई। पूर्व पंद्रह वर्षों से लगातार अंग्रेजी क्लब की ओर से। बानी सर के सौजन्य से। स्ह्लह्वस्रद्गठ्ठह्ल श्द्ध ह्लद्धद्ग 4द्गड्डह्म्-ड्ड2ड्डह्म्स्र कक्षा नवमी में प्रवेशित नन्हे मुन्ने बच्चे जो चार साल इस विद्यालय में अपने प्रतिभा का परचम लहराते हैं।विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। जिला और राज्य से आदेशीत गतिविधियों में अपनी महती भूमिका निभाते हैं।खेल, स्काउट एंड गाइड, शिष्टाचार और सदाचार, अनुशासन और समर्पण, सांस्कृतिक और सामाजिक जन-जागरूकता में सहयोग करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता रहा है।आज इसी कड़ी में पुनः विद्यालय से तीन बेस्ट स्टूडेंट का चयन किया गया है।इस सूची में प्रथम स्थान हासिल करने वाली बालिका माधुरी सिन्हा (कक्षा 12वीं) रहीं।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। Email : loktantraprahrinews@gmail.com